हिमाचल की प्रगति एवं संस्कृति का दर्पण

गिरिराज

साप्ताहिक

डाक पंजीकरण संख्याः एच.पी./42/एस.एम.एल. 2009 साप्ताहिक आर.एन.आई. 32195/78

घर बैठे गिरिराज पाइये

गिरिराज का आजीवन ग्राहक बनने के लिए सदस्यता शुल्क 1500 **रुपये** बैंक ड्राफ्ट या मनिआर्डर के माध्यम से **निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, शिमला**-2 व वार्षिक सदस्य बनने के लिए सदस्यता शुल्क 140 **रुपये, सम्पादक, गिरिराज साप्ताहिक, शिमला**-171005 के नाम से भेजे। पते में पिन कोड एवं दूरभाष या मोबाइल नं. लिखना न भूलें

इस अंक में

कृषि/बागबानी/विकास... 5
आस्था/संस्कृति/विविध... 6
विविध... 7
साहित्य... 8
महिला/बाल जगत/स्वास्थ्य ... 9
पहाड़ी पृष्ठ 10

वर्ष 31 अंक 43 शिमला, 29 जुलाई–4 अगस्त, 2009 हर बुधवार को प्रकाशित मूल्य : एक प्रति 3.00 रुपये वार्षिक 140 रुपये आजीवन 1500 रुपये website : himachalpr.gov.in/giriraj.asp

राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव व मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल शिमला में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक के दौरान सैनिकों के लिए आरंभ की गई कल्याण योजनाओं पर विचार-विमर्श करते हुए

वाकनाघाट में खुलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी पार्क

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत ऐसी सभी श्रेणियों की महिला कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिन्हें सीसीएस (अवकाश) नियम के दायरे में नहीं लाया गया था। मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के वाकनाघाट में 460 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 65 एकड़ सरकारी भूमि पर विश्व स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए निजी निवेशकों से डिजाइन, विकास तथा निर्माण के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया, जिससे राज्य के 25 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस निविदा के लिए वित्तीय क्षमता तथा अनुभव मुख्य पात्रता होगी। प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में बाह्य अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सुविधाकारक की भूमिका अदा करेगी। स्थानीय लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी एहतियाती पग उठाए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को शिक्षा विभाग में टीजीटी नॉन मेडिकल के 224 प्रार्थियों को नियुक्त करने की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने निदेशक तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सिफारिशों पर 139 एससीवीटी केन्द्रों की स्वीकृति को मंजूरी प्रदान की, जो होटल प्रबन्धन, जन संचार, ट्रैवल एंड टूरिज्म, पम्प आप्रेशन, विपणन एंड विज्ञापन, मोटर वाईडिंग, ब्यूटीफिकेशन, एलएमवी ड्राईवर एवं मैंटीनेंस मैकेनिक्स, मल्टी मोटर वाईंडिंग, पलम्बिंग एंड सेनिटेशन, टैक्सटाइल टैक्निशियन, टैक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग जैसे विषयों में कोर्सों का संचालन करेंगे। प्रत्येक केन्द्र द्वारा उक्त कोर्सों में से एक समय में चार से अधिक कोर्सों का संचालन नहीं किया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश शिक्षण संस्थान (रैगिंग निरोधक) बिल, 2009 तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी बिल, 2009 के प्रारूप को आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश अधोसंरचना विकास बोर्ड की संतुति के आधार पर मंत्रिमण्डल ने सभी स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों से वर्ष भर खुली पहुंच को भी स्वीकृति प्रदान की। पांच मेगावाट तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को रियायती रायल्टी सुविधा तभी उपलब्ध होगी यदि वे ऊर्जा हिप्र राज्य विद्युत बोर्ड और इसके प्रतिनिधि निकाय को आपूर्ति करेंगी।

मंत्रिमण्डल ने 40 मेगावाट की बागी जल विद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के माध्यम से निष्पादन करने की अनुमति प्रदान की, बशर्ते बोर्ड प्रदेश को रायल्टी के रूप में 12 प्रतिशत नि:शुल्क विद्युत तथा 'बस बार टैरिफ' के आधार पर वास्तविक ऊर्जा का 15 प्रतिशत प्रदेश को उपलब्ध करवाएगी। बीबीएमबी को इस परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए सभी कार्य निष्पादन स्तरों पर 30 प्रतिशत स्टाफ राज्य विद्युत बोर्ड से डेपुटेशन पर लेना होगा तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा (शेष पृष्ठ 11 पर)

मंत्रिमण्डल के निर्णय

- 'मातृत्व लाभ' अधिनियम के तहत सभी महिला कर्मियों को मातृत्व लाभ।
- वाकनाघाट में 460 करोड़ का आईटी पार्क।
- टीजीटी नान मेडिकल में 224 पद भरे जाएंगे।
- 40 मेगावाट बागी परियोजना का निष्पादन करेगा बीबीएमबी
- दो टोल टैक्स बेरियर खोलने को अनुमति।
- 139 एससीवीटी केन्द्रों को स्वीकृति।

सरकार अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध–प्रो. धूमल

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के तीव्र उत्थान के प्रति प्रदेश सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण को अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति उप योजना के तहत वर्ष 2007–08 में पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान निर्धारित 231 करोड़ रुपये को बढ़ाकर वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008–09 में 594 करोड़ रुपये किया गया है, जो कि कुल राज्य योजना का 24.75 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आबादी 24.72 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के बजट प्रावधान को बढ़ाकर 668 करोड़ रुपये किया गया है, जो कि राज्य की वार्षिक योजना का 24.75 प्रतिशत है।

राज्य योजना का 24.75 प्रतिशत अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत व्यय

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पूर्व शासनकाल के दौरान 2002–03 से 2006–07 में दसवीं योजना में 722.22 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जो कुल राज्य योजना का 9.37 प्रतिशत है।

प्रो. धूमल ने कहा कि अनुसूचित जाति उप योजना के लिए वर्ष 2007–08 से एकल समेकित मांग का सृजन किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति उप योजना के तहत सभी विभागों के बजट आवंटन को शामिल किया गया है तथा इस मांग को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रण में रखा गया है, ताकि अनुसूचित जाति उप योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को (शेष पृष्ठ 11 पर)

आम स्थानांतरण पर प्रतिबंध जारी रहेगा

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में गत दिनों शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि इस शैक्षणिक सत्र के दौरान आम स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रदेश सरकार आम तौर पर हर वर्ष अप्रैल व मई महीनों के दौरान, जब शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र आरंभ होता है तो स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाती है। परन्तु इस वर्ष लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत अप्रैल तथा मई, 2009 के दौरान लागू आचार संहिता के कारण आम स्थानांतरण पर से प्रतिबंध हटाना अथवा सामान्य स्थानांतरण के आदेश जारी करना संभव नहीं था। शैक्षणिक सत्र 2009–10 के लिए प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, इसलिए सभी पहलुओं के मद्देनजर छात्रों व उनके अभिभावकों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि इस शैक्षणिक सत्र के दौरान आम स्थानांतरण पर प्रतिबंध जारी रहेगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।

बीस सूत्री कार्यक्रम में हिमाचल प्रथम

हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर 20–सूत्री कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त कर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2008–2009 के फरवरी माह तक, जिसके पश्चात इस वित्तीय वर्ष का केवल एक माह ही शेष बचता था, में प्रदेश ने 92 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर 20–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सही परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित कर देश को राह दिखाई है। यह उपलब्धि गुजरात से दो प्रतिशत, उत्तराखंड से चार प्रतिशत और आध्रप्रदेश से पांच प्रतिशत अधिक है। हिमाचल सहित ये तीन राज्य 20–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देश के चार सर्वश्रेष्ठ राज्यों के रूप में आंके गए हैं।

- गरीब एवं कमजोर वर्गों के कल्याण की वचनबद्धता पर सरकार की मोहर
- 1.54 करोड़ श्रम दिवस सृजित
- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत उपलब्धि 517 प्रतिशत
- स्वयं सहायता समूहों के गठन की उपलब्धि 104 प्रतिशत
- 49 हजार गरीब परिवारों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान
- आंगनबाड़ी केन्द्रों को कार्यशील बनाने में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल

20–सूत्री कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आवासीय सुविधा, शिक्षा, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य ऐसी योजनाएं शामिल हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती हैं।

रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में इस समयावधि के दौरान 8,17,364 रोजगार कार्ड जारी किए गए और 1.54 करोड़ श्रम दिवस के समकक्ष रोजगार सृजित किया गया, जिसके एवज् में उन्हें 171 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। व्यक्तिगत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश की उपलब्धियां 517 प्रतिशत रही। इस वर्ष के दौरान राज्य में 8619 व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान किया गया, जबकि लक्ष्य 1886 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना था। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक का स्थान है, जिसकी उपलब्धि 470 प्रतिशत रही है। प्रदेश की इन उपलब्धियों से राज्य के अभूतपूर्व कार्य निष्पादन का पता चलता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य की उपलब्धि 318 प्रतिशत है। अप्रैल, 2008 से फरवरी, 2009 के मध्य इस योजना के अन्तर्गत 3486 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और 5612 महिलाओं को स्वरोजगार अर्जित करने में सहायता प्रदान की गई।

स्वयं सहायता समूहों के गठन में हिमाचल प्रदेश ने 104 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की है। इस समयावधि में राज्य में 603 के लक्ष्य के मुकाबले 6630 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। खाद्य सुरक्षा (अन्त्योदय अन्न योजना) के अन्तर्गत राज्य की उपलब्धि 102 प्रतिशत रही है। फरवरी 2009 तक हिमाचल प्रदेश में इसके अन्तर्गत 77,580 टन खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य ने 4.21 लाख टन खाद्य पदार्थ वितरित कर लगभग शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की उपलब्धि 103 प्रतिशत रही है। राज्य में इस समयावधि के दौरान 4410 के लक्ष्य के मुकाबले 4610 बस्तियों को (शेष पृष्ठ 11 पर)

एक करोड़ औषधीय पौधे रोपे जाएंगे

वन मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पिछले वर्ष 'जन–जन संजीवनी वन अभियान' आरम्भ किया गया जिसमें प्रदेश के ग्रामीण व शहरी इलाकों के लोगों ने 15 लाख से भी अधिक औषधीय प्रजाति के पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाने के लिए प्रदेश में वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत बनाई गई 'सांझा वन प्रबन्धन समितियों' को सम्मिलित किया जा रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रदेश की ऐसी 525 सक्रिय 'सांझा वन प्रबन्धन समितियों' के सहयोग से 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग एक करोड़ औषधीय प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे।

यह जानकारी वन मंत्री ने गत दिनों शिमला में वरिष्ठ वन अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी जिसमें वन विभाग द्वारा इस वर्ष किए जाने वाले पौधरोपण की तैयारियों की समीक्षा की गई।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) श्री अभय शुक्ला तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

1.28 लाख किसानों के कृषि ऋण माफ

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में कर्जा माफी तथा ऋण राहत योजना–2008 के तहत राज्य में विभिन्न सहकारी बैंकों के 1,27,211 सदस्यों के 211.50 करोड़ रुपये के कृषि ऋण मामलों को माफ किया गया है, जिसमें से लाभार्थियों को 118.44 करोड़ रुपये के लाभ सुनिश्चित बनाये जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत प्रत्येक पात्र कर्जदार को ऋण माफी योजना के लाभ सुनिश्चित बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को प्रदेश तथा केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं के लाभ उठाने के लिए प्रेरित किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही ऋण सुविधाओं के बारे में बताने के लिए जागरुकता अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। यह जानकारी मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों शिमला में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए दी।

प्रदेश सरकार राज्य में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध करवाएगी तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 'हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता सहकारी सभाएं' नामक नये विधेयक को तैयार कर इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। यह विधेयक भारत सरकार की समितियों द्वारा प्राथमिक सहकारी सभाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुझाए गए आदर्श नियमों पर आधारित होगा, जिनमें प्रदेश सरकार को यह अधिकार होगा कि सहकारी सभाओं की गतिविधियों की आवधिक समीक्षा कर इनके सदस्यों की जमा राशियों को सुरक्षित रख सकें।

'हि.प्र. आत्मनिर्भरता सहकारी सभाएं विधेयक' लागू करना विचाराधीन

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण युवाओं के लिए रोज़गार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में सहकारी सभाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जिससे ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सहकारी सभाएं अधिनियम 1968 तथा हिमाचल प्रदेश सभाएं अधिनियम–2006 में संशोधन पर भी विचार किया जा सकता है ताकि सभा निकायों के निर्णयानुसार प्राथमिक सभाओं के जमाकर्ताओं को पूर्ण मताधिकार तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट करवाने की सुविधा प्रदान की जा सके, जबकि विशेष ऑडिट रजिस्ट्रार द्वारा ही किया जाएगा।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 1948 में 18375 की सदस्यता के साथ 663 सहकारी सभाओं की तुलना में वर्ष 2009 में 4426 कार्यशील सहकारी सभाओं की सदस्यता संख्या 14 लाख से भी अधिक हो गयी है, जिनमें 10,392.25 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी, 7663.46 करोड़ का निवेश सुनिश्चित बनाकर शत प्रतिशत गावों को सहकारिता के दायरे में लाया गया है।

सचिव सहकारिता डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने सहकारिता विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल शिमला में जनसमस्याओं का निपटारा करते हुए

सभी पुलिस थाने होंगे 'ऑन लाइन'

प्रदेश के सभी 101 पुलिस थानों को चालू वित्त वर्ष के अन्त तक 'ऑन लाइन' कर दिया जाएगा जहां शिकायतकर्ता 24 घंटे कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने यह जानकारी गत दिनों शिमला में गृह विभाग के विभिन्न प्रभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 90 पुलिस थानों में शिकायतों का 'ऑन लाइन' पंजीकरण आरम्भ कर दिया गया है और शेष 11 पुलिस थानों को वर्ष 2009–10 के दौरान आवश्यक सुविधाओं से लैस कर शतप्रतिशत 'हाईटेक' का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यातायात चालानों की 'ऑन लाइन' भुगतान सुविधा आरम्भ कर दी गई है ताकि चालान शुल्क जमा करवाने के लिए लोगों को इधर-उधर न भटकना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम्प्यूट्रीकृत 90 थानों में शिकायतकर्ताओं के लिए दूरभाष न. 100 टोल-फ्री सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि स्थानीय पुलिस के साथ जरूरत पड़ने पर सम्पर्क कायम रखा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत वर्ष तीन पुलिस थानों को उच्च मानक व्यावसायिक सेवाओं के लिए आई.एस.ओ. प्रमाणित किया गया है, जबकि चालू वित्त वर्ष के दौरान 12 और पुलिस थानों को इससे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाना में महिला कांस्टेबल तथा बाल सहायता इकाई सुविधा उपलब्ध है ताकि महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अत्याचार के मामलों में कारगरता से निपटा जा सके।

- स 90 थानों में 'टोल फ्री' शिकायत सुविधा उपलब्ध
- स 11 थानों में 'टोल फ्री' सुविधा इसी वर्ष।

मुख्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल पुलिस को देशभर के पुलिस बल संगठनों में वर्ष 2008 में ई-शासन के तहत पुलिस वैब पोर्टल सेवा के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय सम्मान हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस बल आधुनिकीकरण कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक स्थानों व शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास मादक द्रव्यों के सेवन पर अंकुश लगाने के लिए कड़े उपाए करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भांग तथा अफीम की खेती में संलिप्त लोगों को नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दुर्घटना सम्भावित स्थलों को चिन्हित करें तथा वहां चेतावनी पट्टिकाएं लगाएं। उन्होंने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों, अस्पतालों तथा सार्वजनिक स्थलों पर खड़े वाहन मालिकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के लिए विशेषज्ञ-जांच के लिए 'केश कोर्स' आयोजित करने पर भी बल दिया ताकि वे अपना कार्य निष्पादन और बेहतर ढंग से कर सकें।

मुख्य सचिव श्रीमती आशा स्वरूप ने कन्या भ्रूण हत्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

सामुदायिक सौहार्द का संगम मिंजर मेला

हिमाचल प्रदेश के इतिहास में चम्बा जनपद का विशेष स्थान है। चम्बा शहर ने अपने अस्तित्व के एक हजार वर्ष पूर्ण किये हैं। चम्बा जिला गौरवमयी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का खजाना है तथा आज भी यहां के निवासियों ने आधुनिकता के प्रभाव के बावजूद इसे संजोकर रखा है।

चम्बा में 1908 में उत्तर भारत का पहला बिजली घर स्थापित हुआ था। वहीं यहां के हस्तशिल्प चम्बा रूमाल व चम्बा चप्पल ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। करीब दस शताब्दियों से चम्बा ने ऐसे-ऐसे मील पत्थर स्थापित किए जिनका अस्तित्व और महत्व आज भी बरकरार है। चम्बा के जनमानस ने अमर लोकगीत व संगीत की रचना करके यहां की समग्र लोक संस्कृति को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जो किसी परिचय का मोहताज नहीं।

रावी नदी के तट पर बसे इस खूबसूरत पहाड़ी नगर में जुलाई-अगस्त में आयोजित होने वाले मिंजर मेले में सम्पूर्ण जनपद की लोक संस्कृति, लोक मानस, इतिहास व सामुदायिक सद्भावना की झांकी देखने को मिलती है। प्रत्येक लोक मेले की तरह मिंजर मेले के आरम्भ की पृष्ठभूमि से भी जनश्रुतियां जुड़ी हैं। लोक धारणा के अनुसार मिंजर मेला चम्बा के शासक की पड़ोसी राज्य पर विजय के उल्लास का प्रकटीकरण है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार रावी नदी प्राचीन समय में वर्तमान चौगान मैदान से होकर बहती थी। नदी के उस पार स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए तैर कर जाना पड़ता था। समस्या के निदान को लेकर राज पुरोहित ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान एक पवित्र रस्सी बनाई गई जिसे मिंजर नाम दिया गया। कहते हैं कि यज्ञ की पूर्णाहूति के बाद रावी ने अपना बहाव बदल दिया।

कुछ विद्वानों का मत है कि मिंजर मेले का आयोजन वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ताकि खेत-खलिहानों में अच्छी फसल हो। इतिहासविदों का एक वर्ग यह मानता है कि जब चम्बा के राजा विजय प्राप्त करने के उपरांत वापिस अपनी रियासत में लौटे तो प्रजा ने विजयोपहार के तौर पर मक्की के पौधों के शीर्ष पर उगने वाली 'मिंजरें' राजा को भेंट की थीं। तत्पश्चात यही विजय पर्व मिंजर मेला कहलाया।

मेले के सम्बन्ध में किंवदंतियां अथवा लोक धारणाएं जो भी हों पर यह तय है कि मिंजर मेला चम्बा के बीते कल की खुशहाली व सम्पन्नता का प्रकटीकरण तो है ही साथ ही पुरातन धार्मिक आस्थाओं, सामाजिक मान्यताओं व लोक संस्कृति के अन्य पहलुओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवंत रखे जाने का लोक आयोजन भी है।

श्रावण महीने के दूसरे रविवार से शुरू होकर तीसरे रविवार तक मनाये जाने वाले मिंजर मेले में भी अन्य मेलों व उत्सवों की भांति सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाता है। मेले का अब व्यापारिक महत्व भी बढ़ा है। पर मिंजर मेले के साथ धार्मिक सौहार्द की जो मिसाल चली आ रही है वह अपने आप में अनुकरणीय व अनुपम है। मेले के शुभारम्भ पर भगवान लक्ष्मीनारायण और रघुवीर को सबसे पहले एक मुस्लिम परिवार मिंजरें अर्पित करता है। यह परिवार रियासती जमाने से ही मिंजरें तैयार करता आ रहा है। राजा पृथ्वी सिंह के साथ मुगल बादशाह शाहजहां ने जरी के काम में माहिर कलाकार मिर्जा शफी बेग को भेजा था। उसी कलाकार की पीढ़ियां ने इस परम्परा को सहेज कर रखा है।

मिंजर मेला चम्बा के लोगों के मन में इस कद्र रचा बसा है कि भारत-पाक बंटवारे के दौरान चम्बा से जो मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गये थे वे काफी समय तक वहां की सरजमीं पर भी मिंजर उत्सव मानते रहे। आज भी चम्बा से दूर ब्याही बेटियां मिंजर में आने का मोह रखती ही हैं चाहे वे किसी भी समुदाय विशेष से क्यों न हों।

मिंजर मेले के समापन पर रविवार को सायं अखंड चंडी महल से निकलने वाली शोभायात्रा का आज उतना ही आकर्षण रहता है जितना कभी उस वक्त था जब रियासत के राजा हाथी पर सवार होकर शोभायात्रा की अगुवाई किया करते थे। सड़क के दोनों ओर खड़ा लोगों का हुजूम शोभायात्रा का दोपहर से ही बड़ी बेसब्री से इंतजार करता रहता है। शोभायात्रा का समापन रावी नदी क किनारे नलहोग नामक स्थान पर होता है। यहां पर लोग मंगलकामना के साथ नारियल फल, मिंजर, सिक्के व मौसमी फलों को नदी में प्रवाहित करते हैं। मिंजर को प्रवाहित करने की इस रस्म के साथ ही मेले का समापन भी हो जाता है।

शोभायात्रा में शामिल भगवान रघुवीर की पालकी समेत अन्य देवी-देवताओं की पालकियां शाही ध्वजों व चिन्हों के साथ वापिस आ जाती हैं। मिंजर मेले की एक अन्य विशिष्टता मेले के दौरान गाये जाने वाले पारम्परिक कूंजड़ी-मल्हार गीत हैं। मेले का आरम्भ व समापन भी इन्हीं गीतों के साथ होता है। कूंजड़ी-मल्हार का गायन चम्बा के विशिष्ट लोकगायकों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है।

–रवि वर्मा

अनुराग ठाकुर बने पीजीआई चण्डीगढ़ के सदस्य

लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री अनुराग ठाकुर को चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान (पी.जी.आई.) चंडीगढ़ का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

श्री अनुराग ठाकुर वर्ष 2008 में 14वीं लोकसभा के लिए पहली बार तथा वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुए। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष श्री ठाकुर 25 वर्ष की आयु में राज्य क्रिकेट संघ के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष तथा वर्ष 2001 में भारतीय जूनियर क्रिकेट टीम के सबसे कम आयु के राष्ट्रीय चयनकर्ता बने।

उन्होंने विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों में शामिल होकर यू.एस.ए., यू.के., आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, स्विट्ज़रलैण्ड तथा जर्मनी जैसे विभिन्न देशों का भ्रमण किया है।

मुख्य मंत्री की हिमाचल प्रदेश को रैगिंग मुक्त बनाने की अपील

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के सभी शिक्षा संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों एवं विद्यार्थियों से बेहतर शैक्षणिक वातावरण सृजित कर हिमाचल प्रदेश को रैगिंग मुक्त राज्य बनाने में सहयोग करने की अपील की है ताकि नये छात्र तनाव मुक्त एवं भय मुक्त होकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। मुख्य मंत्री गत दिनों शिमला में सेंट बीडज कालेज द्वारा आयोजित 'फ्रैशर डे' समारोह के अवसर पर बोल रहे थे।

मुख्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल एवं उनकी शिक्षा गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत विकास के अतिरिक्त, शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों में सेंट बीडज कालेज अग्रणी संस्थान रहा है। उन्होंने कहा कि नव आगन्तुक विद्यार्थियों के लिए आयोजित यह कार्यक्रम एक अच्छी शुरुआत है तथा यह रैगिंग जैसे जघन्य कार्य का एक जबाव है। उन्होंने कहा कि अन्य शिक्षा संस्थाओं में भी इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे नव आगन्तुक विद्यार्थी रैगिंग के डर की अपेक्षा अपने आप को सुरक्षित समझें और वरिष्ठ विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त कर सकें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कालेज प्रशासन एवं अभिभावकों, शिक्षक संघ, शिक्षा संस्थाओं से रैगिंग को समाप्त करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

शिक्षण संस्थानों में सरकार बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध

प्रो. धूमल ने कहा कि कोई भी कानून समाज के सहयोग के बिना वांछित परिणाम नहीं ला सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश से रैगिंग को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है, जिससे प्रदेश रैगिंग मुक्त राज्य बन सके। उन्होंने लड़कियों की प्रतिभा को और अधिक निखारने में सेंट बीडज कालेज के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान न केवल शिक्षा के केन्द्र हैं, बल्कि सही अर्थों में पढ़ाई के मंदिर भी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का समाज में विशेष स्थान रहा है तथा वर्तमान में भी महिलाओं को पूर्ण सम्मान प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि स्वस्थ एवं सुदृढ़ समाज का निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा कि महिला लिंग अनुपात में गिरावट चिंता का विषय है, जिससे सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो सकता है तथा प्रत्येक जागरूक नागरिक को इस समाधान पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सेंट बीडज कालेज की प्रधानाचार्य सिस्टर डा. मौली अब्राहम ने मुख्य मंत्री का स्वागत किया।

महात्मा गांधी बुनकर योजना के कार्यान्वयन में प्रदेश अग्रणी

महात्मा गांधी बुनकर योजना के बेहतर कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन कर उभरा है। उद्योग मंत्री श्री किशन कपूर ने यह जानकारी गत दिनों शिमला में विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि योजनाओं के लाभ पात्र लोगों तक सुनिश्चित हो सकें। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 8447.16 करोड़ रुपये निवेश की 422 मध्यम एवं बड़ी तथा 35500 माइक्रो एवं लघु कुटीर औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें 2,30,636 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं।

श्री कपूर ने कहा कि प्रदेश का बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र आगामी वित्त वर्ष के अंत तक गैस पाईप लाईन सुविधा से जुड़ने वाला पहला क्षेत्र होगा, जिससे औद्योगिक निवेशकों को सस्ती दरों पर ऊर्जा उपलब्ध होगी तथा औद्योगिक संयंत्र परिसरों में उत्पादन प्रक्रिया में साफ-सफाई बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

- **हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में 45000 बुनकर कार्यरत**
- **9900 परिवार रेशम उत्पादन से जुड़े**

उद्योग मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल के दौरान 80 प्रतिशत चुनावी वायदों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्यमियों की सुविधा के लिए भूमि बैंक स्थापित किया गया है, जहां 1793–17 बीघा सरकारी भूमि तथा 5089–09 बीघा निजी भूमि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में 1078 बीघा निजी भूमि औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध है, जहां बेहतर सड़क सुविधा, ब्रॉडगेज लाईन, हवाई मार्ग सेवा तथा अन्तरराष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विशेष औद्योगिक पैकेज को इसकी वास्तविक अवधि 2013 तक बढ़ाने का मामला भारत सरकार के साथ प्रभावशाली तरीके से उठा रही है।

श्री कपूर ने कहा कि प्रदेश में रेशम उत्पादन को गत वर्ष की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक दाम प्राप्त हुए हैं तथा प्रदेश में रेशम कोकून उत्पादन वर्ष 2007–08 के 105 टन से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 155.29 टन हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9900 परिवार रेशम उत्पादन से जुड़े हैं तथा राज्य में एक रेशम बीज उत्पादन केन्द्र के अतिरिक्त 73 रेशम विस्तार केन्द्र, 89 शहतूत फार्म तथा 30 शहतूत नर्सरियां कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में 45000 बुनकर कार्यरत हैं, जिन्हें समन्वित हथकरघा विकास योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, रियायत व अनुदान योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

निदेशक उद्योग श्री मनोज कुमार ने विभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। प्रधान सचिव उद्योग श्री पी.मित्रा, अतिरिक्त निदेशक एवं एसीएस श्री राकेश शर्मा, औद्योगिक सलाहकार श्री राजेन्द्र चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

तीन माह में होगा वक्फ बोर्ड सम्पत्तियों का सर्वेक्षण

प्रदेश में वक्फ सम्पत्ति की पहचान कर उसे हि.प्र. वक्फ बोर्ड के नाम किया जाएगा, जिसके लिए सम्बन्धित जिला राजस्व अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाली वक्फ सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी राजस्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने गत दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए दी।

ठाकुर गुलाब सिंह ने कहा कि प्रदेश में वक्फ सम्पत्ति को चिन्हित करने के लिए तीन महीनों के भीतर एक सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि ऐसी सम्पत्ति को वक्फ बोर्ड के नाम शीघ्र किया जा सके। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड प्रदेश में चिन्हित की गई वक्फ सम्पत्ति को अतिक्रमण से बचा कर इसका सही प्रबन्धन सुनिश्चित बनाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड सम्पत्तियों का मूलस्रोत, आय तथा इनसे लाभान्वित लोगों के सम्बन्ध में उचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा स्कूलों, मदरसों तथा मस्जिदों के निर्माण के लिए दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता के बारे में उचित मापदण्ड तय किये जाने चाहिए। ठाकुर गुलाब सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा प्रदेश में विभिन्न मस्जिदों के लिए 85 हजार रुपये की तदर्थ ग्रांट प्रदान की जा रही है ताकि धार्मिक संस्थानों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार गतिविधियों का संचालन किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य में 103 मस्जिदों को सात लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की आय में वृद्धि करने के लिए वक्फ सम्पत्तियों के कम किराए के मामलों को शीघ्र सुलझाया जाना चाहिए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शिमला के बालूगंज में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के कार्यालय का निर्माण किया जाएगा, जहां बोर्ड के नाम 1647.90 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध है।

शिमला में निर्मित होगा वक्फ कार्यालय

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व सुश्री हरिन्द्र हीरा ने कहा कि शिमला क्षेत्र में वक्फ सम्पत्ति के चार अवैध कब्जों को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील में भवारना में एक मस्जिद को न्यायालय से बाहर आपसी रजामंदी द्वारा खाली करवाया गया है। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ए.डब्ल्यू खान ने कहा कि बोर्ड के सीधे प्रबन्धन में कार्यरत इमामों तथा परिचारकों को वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न मस्जिदों में 22 इमामों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें मस्जिद प्रबन्धन समितियों के माध्यम से 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये मासिक तक की ग्रांट दी जा रही है।

भू–दान यज्ञ बोर्ड की बैठक आयोजित

श्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भू-दान के माध्यम से एकत्रित भूमि को निर्धन एवं पात्र लोगों को आवंटित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भू-दान यज्ञ बोर्ड की कम से कम 1/5 भूमि को राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को देने के लिए आवंटित किया गया है।

राजस्व मंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि उनके पास उपलब्ध फालतू भूमि का उदारता से दान करें ताकि इसे भूमिहीन जरूरतमंद लोगों को दिया जा सके। उन्होंने कहा कि भू-दान दी गई जमीन, मुकदमेबाजी से मुक्त होनी चाहिए ताकि सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा इसकी निशानदेही की जा सके।

विशेष सचिव राजस्व श्री एल.आर. चौहान ने बोर्ड द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व सुश्री हरिन्द्र हीरा, सचिव राजस्व श्री राकेश कौशल, राजस्व विभाग के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी तथा बोर्ड के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

19 हजार हेक्टेयर क्षेत्र बागबानी के तहत लाया गया

बागबानी मंत्री श्री नरेन्द्र बरागटा ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2009–10 के लिए केन्द्रीय सहायता जनजातीय योजना के तहत 238.57 लाख रुपये तथा अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत 40 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। श्री बरागटा ने यह जानकारी गत दिनों शिमला में आयोजित बागबानी विभाग की समीक्षा बैठक में दी।

श्री बरागटा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 8963 लाख रुपये लागत की एक कार्य योजना भारत सरकार को प्रेषित की थी, जिसके तहत राज्य को 2000 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2009–10 के लिए 2050 लाख रुपये लागत की एक अन्य कार्य योजना भारत सरकार को स्वीकृति के लिए प्रेषित की गई है।

बागबानी मंत्री ने कहा कि बागबानी तकनीकी मिशन के तहत 19376 हेक्टेयर क्षेत्र को फलदार पौधों, 3044 हेक्टेयर क्षेत्र को सब्जियों, 253.8 हेक्टेयर क्षेत्र को पुष्प खेती 562.3 हेक्टेयर क्षेत्र को औषधीय पौधे तथा 641.6 हेक्टेयर क्षेत्र को मसालों की खेती के अधीन लाया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1470 जल भण्डारण निर्मित किए गए हैं। राज्य में किसानों एवं बागबानों को 3843 उच्च तकनीक मशीनें, 418 पावर टिलर तथा 350 डीजल इंजन वितरित किए गए हैं।

सचिव बागबानी श्री राम सुभग सिंह ने विभाग के अधिकारियों को परामर्श दिया कि प्रदेश की जलवायु के लिए अनुकूल विदेशी फल पौधे एवं मूलवृन्त प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए।

धर्मपुर में खुलेगा पथ परिवहन निगम डिपू

धर्मपुर में हिमाचल पथ परिवहन निगम का डिपू खोला जाएगा। यह जानकारी परिवहन, शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने गत दिनों धर्मपुर में एक करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले बस अड्डे का शिलान्यास करने के बाद एक भारी जनसभा को सम्बोधित करते हुए दी।

इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्थीय विकास के लिए केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने को कहा।

विधायक कर्नल इन्द्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

मण्डी तथा गोहर न्यायिक परिसरों का लोकार्पण

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला ने गत दिनों वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से 3 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से मण्डी में निर्मित न्यायिक परिसर का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से अपने सम्बोधन में न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला ने कहा कि इस परिसर के निर्माण से न्यायिक अधिकारियों तथा बार संघ के पदाधिकारियों को लोगों को शीघ्र न्याय प्रदान करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने जिला बार संघ के पदाधिकारियों से लोगों को विभिन्न मामलों में शीघ्र न्याय देने में न्यायिक अधिकारियों को अपना सहयोग देने का आह्वान किया ताकि लोगों का न्यायालयों पर विश्वास बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि देरी से न्याय मिलने की वजह से लोगों का न्यायालयों पर विश्वास कम हो जाता है इसलिए न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं का प्रयास होना चाहिए कि लोगों को शीघ्र न्याय प्राप्त हो। उद्घाटन अवसर पर मौजूद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति से ही पहली बार हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से न्यायिक परिसर का उद्घाटन सम्भव हुआ है। उन्होंने कहा कि इस परिसर में न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं द्वारा लोगों को शीघ्र न्याय देने में एक उचित वातावरण एवं सुविधा प्राप्त होगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डी श्री डी.के. शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने गोहर में एक करोड़ चार लाख रुपये की लागत से निर्मित न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया।

मंदिर सुधार समिति रिपोर्ट प्रस्तुत

पूर्व आईएएस अधिकारी श्री के.सी. शर्मा की अध्यक्षता में राज्य में धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्धन में सुधार लाने के लिए गठित हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शक्ति मंदिर सुधार समिति ने सदस्य सचिव श्री प्रेम प्रसाद पंडित के माध्यम से अपनी रिपोर्ट मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल को प्रस्तुत की है।

मुख्य मंत्री ने राज्य के धार्मिक स्थलों के बेहतर प्रबन्धन के बारे में तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट के लिए समिति का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि रिपोर्ट की सिफारिशों को राज्य के अधिसूचित मंदिरों में बेहतर तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने समिति द्वारा रिपोर्ट में दी गई बहुमूल्य सूचनाओं की सराहना की, जिससे मंदिरों के प्रभावी प्रबन्धन में सहायता मिलेगी।

सड़कों के निर्माण के लिए 16.39 करोड़

मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण व उच्च शिक्षा) श्री वीरेन्द्र कंवर ने गत दिनों ऊना में लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करके जिले में सड़कों के निर्माण व रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला ऊना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सड़कों के निर्माण व रखरखाव पर 16.39 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है जिसमें से अब तक 6 करोड़ 86 लाख 59 हजार रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

शिमला श्रेष्ठ पर्यटक स्थल के लिए पुरस्कृत

हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2009 के लिए सीएनबीसी आवाज ट्रैवल के श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है। सीएनबीसी द्वारा यह पुरस्कार भारत की शोध एजेंसी 'साइनोवेट' द्वारा किए गए 'क्लास आर्गेनाइजेशन', स्थानागत अधोसंरचना तथा सेवाएं प्रदान कर्ता पर किए गए व्यापक अध्ययन के आधार पर दिया गया है। शिमला ने वर्ष 2009 के लिए श्रेष्ठ पर्वत/हिल डेस्टिनेशन के लिए सीएनबीसी आवाज पुरस्कार प्राप्त किया है। यह जानकारी सीएनबीसी आवाज के एडिटर इन चीफ ने सचिव पर्यटन श्रीमती मनीषा नन्दा को दी।

गिरिराज

वक्त पर न किया गया कार्य, न करने के बराबर है।
-अज्ञात

एक और बड़ी उपलब्धि

हिमाचल प्रदेश ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम में देश भर में प्रथम स्थान हासिल कर यह सिद्ध कर दिया है कि प्रदेश में गरीबोन्मुखी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन हो रहा है। प्रदेश द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 92 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सही परिप्रेक्ष्य में लागू कर देश को राह दिखाई है। अर्जित उपलब्धियां गुजरात, उत्तराखण्ड तथा आंध्रप्रदेश से अधिक हैं। ये सभी राज्य विकास के मामले में प्रदेश से कहीं आगे थे, जिन्हें हिमाचल ने पीछे छोड़ दिया है। यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से आम आदमी का कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करना आज समय की मांग है। ताकि गांवों से पलायन को रोककर रोजगार के अवसर घर-द्वार पर उपलब्ध हों। राज्य भर में 1.54 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यही नहीं स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की उपलब्धि भी 157 प्रतिशत अर्जित की गई है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा सूचना के तीव्रता से गांव- गांव तक सुलभ होने के कारण ग्रामीणों ने आज स्वयं सहायता की अवधारणा को भी अपनाया है। इसके तहत महिलाओं में एक नई जागरूकता का सूत्रपात हुआ है तथा 104 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करना ग्रामीणों में आर्थिक उत्थान के प्रति आ रही सामूहिक सोच एवं जागरूकता का ही परिणाम है। असमय मानसून तथा आर्थिक मंदी ने दुनिया भर में असर डाला है। इससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ौतरी दर्ज हुई है। गरीब तथा अति निर्धनतम परिवारों को कम मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं को नियमित तौर पर उपलब्ध करवाकर सरकार ने गरीबी उन्मूलन की कटिबद्धता को साबित किया है। साथ ही अनुसूचित जाति कल्याण, एकीकृत बाल विकास तथा वानिकी कार्यक्रमों ने भी प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम ने यह पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान सरकार ने ग्रामीण जनमानस की आवश्यकताओं एवं जरूरतों को भली भांति समझा है। इस उपलब्धि से सरकार के इस दिशा में उठाये गये कदमों को और तेजी मिलेगी। हाल ही में मुख्य मंत्री ने निर्माणाधीन विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए इनका नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश देकर यह संकेत दिया है कि सरकार उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि प्रदेश को शीघ्र आत्मनिर्भर एवं प्रत्येक व्यक्ति का तीव्र सामाजिक आर्थिक उत्थान कर इस छोटे से प्रदेश को विकास का एक आदर्श राज्य बनाने के प्रति गंभीर है। गांव-गांव तक सड़क सुविधा, औद्योगिक एवं ऊर्जा विकास, कृषि-बागबानी आर्थिकी को सुदृढ़ता, गरीबों एवं बेसहारा परिवारों को आर्थिक मदद, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विस्तार ने सही मायनों में सम्पूर्ण प्रदेश में विकास की मूक क्रांति का सूत्रपात किया है। वर्तमान सरकार की उपलब्धियों में पर्यावरण संरक्षण के लिए डायमंड स्टेट अवार्ड, जन-जन संजीवनी अभियान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मण्डी में आईआईटी व मेडिकल कॉलेज, भानुपल्ली-बिलासपुर-मण्डी-मनाली लेह रेलमार्ग, निवेश माहौल, प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में प्रथम स्थान तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम में देश भर में प्रथम स्थान हासिल करना एक और मील का पत्थर जुड़ जाना है। इसके लिए मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में वर्तमान सरकार बधाई की पात्र है। यह 18 माह में प्रदेश में सुशासन एवं आम आदमी को लाभान्वित करने की वचनबद्धता को भी दर्शाता है। इस उपलब्धि से आम आदमी की सरकार के प्रति विश्वसनीयता और बढ़ेगी।

पहाड़ और परमार

डॉ. यशवन्त सिंह परमार ने 15 अप्रैल, 1955 को जो विचार व्यक्त किये थे, वे आज इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश के लिए सच साबित हुए हैं। उन्होंने कहा था, 'हमें अपने स्वर्णिम भविष्य में विश्वास है, इसलिए कुछ ही वर्षों में हिमाचल प्रदेश न केवल आत्म-निर्भर होगा बल्कि यह भारतीय संघ की एक सम्पन्न इकाई के रूप में देश की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान भी देगा।'

आज हिमाचल देश को ऊर्जा की आपूर्ति, विभिन्न कृषि व बागबानी उत्पाद, पर्यटकों के लिए सैरगाहें तथा शिक्षा के अनेक मंदिरों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है।

डॉ. परमार लोकप्रिय जननायक, निष्पक्ष न्यायाधीश, कृषि एवं बागबानी प्रेमी तथा पहाड़ी संस्कृति के पोषक थे। इसके अतिरिक्त उनका स्थान गंभीर विचारक, साहित्यकार, कुशल प्रशासक एवं पर्वतीय राज्य के मददगार के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है।

डॉ. परमार का जन्म 4 अगस्त, 1906 को तत्कालीन सिरमौर रियासत के बागथन के समीप चन्हालग गांव में हुआ। पिता भण्डारी शिवानन्द सिरमौर रियासत के दो महाराजाओं के सचिव थे। डॉ. परमार ने बचपन में ही अपने माता-पिता से प्राचीन कला, संस्कृति एवं एक कुशल प्रशासक का ज्ञान हासिल किया। डॉ. परमार ने राजकीय हाई स्कूल, नाहन से वर्ष 1922 में दसवीं की शिक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा लाहौर के प्रसिद्ध क्रिश्चियन कॉलेज फॉर मैन से हासिल की। इसी कॉलेज से उन्होंने 1926 में बीए (आनर्स) की उपाधि अर्जित की। तदोपरान्त केनिंग कॉलेज लखनऊ से 1928 में एमए तथा एलएलबी की उपाधि ली। वर्ष 1944 में डॉ. परमार ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही 'सोशियो एकोनोमिक ग्राउंड ऑफ हिमालयन पोलिएंडरी' विषय पर पीएचडी की उपाधि हासिल की। वर्ष 1929-30 में डॉ. परमार थियोसोफिकल सोसायटी देहरादून के सदस्य बने और इसी वर्ष वकालत आरम्भ की। वर्ष 1930 में सिरमौर रियासत में सब-जज नियुक्त हुए। इस दौरान देश भर में स्वतन्त्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। तथा इसके साथ ही पहाड़ी राज्य में प्रजातंत्र आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। स्वतन्त्रता आंदोलन से प्रभावित हो और अपनी न्यायप्रियता को समझते हुए डॉ. परमार ने नौकरी व सिरमौर को छोड़ दिया।

स्वतन्त्रता आंदोलन का नेतृत्व

लाहौर के समीप मीयां मीर में रहते हुए डॉ. परमार पझौता आंदोलनकारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार बारे अप्रत्यक्ष रूप से स्वतन्त्रता सेनानियों की सहायता करते रहे। वर्ष 1943 से 1946 तक दिल्ली स्थित सिरमौर एसोसिएशन के सचिव बने और 1946-47 में हिमाचल पहाड़ी राज्य परिषद के अध्यक्ष। सन् 1957-48 में ग्रुपिंग एण्ड अमलगामेशन कमेटी, ऑल इंडिया पीपल्स कांफ्रैंस के सदस्य, प्रजामण्डल सिरमौर के अध्यक्ष और सुकेत स्वतन्त्रता आंदोलन के मुख्य संचालक के पदों पर रहकर आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।

वर्ष 1946 से 1948 तक डॉ. परमार ने अनेक मंचों पर पृथक हिमाचल के गठन की आवाज उठाई तथा 15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल की स्थापना एक चीफ कमिश्नर के अधीन हुई। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल के गठन का श्रेय डॉ. परमार को जाता है। इसलिए वे हिमाचल निर्माता के नाम से भी जाने जाते हैं।

हिमाचल का वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय भी डॉ. परमार को जाता है। पहली नवम्बर 1966 के शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर डॉ. परमार ने कहा था, 'आज एक मुद्दत से पिछड़े लोग आपस में मिल रहे हैं। हिमाचलवासियों के लिए स्वतन्त्रता संग्राम का यह चरण भी पूर्ण हुआ। हमारा आज का मिलन हमारी भाषा और अद्वितीय संस्कृति के आधार पर संभव हो सका। ...हिमालय के इस शस्य श्यामल भू-भाग को, जिस पर प्रकृति ने अपना पूरा प्यार उड़ेल रखा है और अपनी सारी सुन्दरता न्योछावर कर रखी है। नये हिमाचल का सूत्रपात सब पहाड़ी निवासियों को सुख समृद्धि एवं आत्म सम्मान से विभूषित कर भारतीय जन समाज में बराबरी का दर्जा देगा, तब इन पहाड़ों का नाम ऊंचा होगा।'

25 जनवरी, 1972 को हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिलाने में भी डॉ. परमार का योगदान महत्वपूर्ण है।

पहाड़ी भाषा एवं संस्कृति

पहाड़ी भाषा तथा संस्कृति को बढ़ावा देने में डॉ. परमार ने अहम योगदान दिया। उनके शब्दों में, 'पहाड़ी जिसे अब तक बोली समझा जाता था, दरअसल 30 लाख हिमाचल वासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और मुझे आशा है कि इसे यथा समय संवैधानिक दर्जा दे दिया जायेगा।'

पहाड़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जो डॉ. परमार ने किया है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। 20 जुलाई, 1971 को अपने सम्बोधन में डॉ. परमार ने कहा था, 'संस्कृति पर भी हमले हुए हैं। अंग्रेजों ने संस्कृति के ह्रास की कोशिश की। लेकिन हमने अपनी संस्कृति को बचाकर रखा।'

अपने कार्यकाल के दौरान डॉ. परमार ने प्रदेश के समग्र विकास की अवधारणा को ही नहीं अपनाया बल्कि इसके आत्म-निर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाये।

विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के शब्दों में, 'यदि भारत में आज हिमाचल प्रदेश एक सेब राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो उसका प्रमुख श्रेय यशवन्त सिंह परमार को जाता है।'

डॉ. परमार के शब्दों में, 'बागबानी हिमाचल का जीवन है। हिमाचल का भविष्य भी बागबानी पर निर्भर करता है।' बागबानी के अतिरिक्त डॉ. परमार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए त्रिमुखी खेती की अवधारणा को बढ़ावा दिया। अनेक वन महोत्सवों पर वह भगवान बुद्ध का उपदेश दोहराया करते थे कि भिक्षुओं को वैवाहिक सुख संतति तथा पुत्र-पुत्री से सम्पन्न न होने से निराश न होकर अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाकर अपनी स्मृति बनाये रखनी चाहिए। इसी तरह हमें उनसे ज्ञान लेकर पौधरोपण को बढ़ावा देना चाहिए।

प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा गांवों के विकास के लिए डॉ. परमार ने प्रदेश के आरम्भिक वर्षों में जल विद्युत उत्पादन तथा सड़क निर्माण को विशेष महत्व दिया। डॉ. परमार का प्रदेश को विकास पथ पर आगे बढ़ाने के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनका सम्पूर्ण जीवन राजनैतिक संघर्ष की एक वीरतापूर्ण गाथा है। डॉ. परमार में पहाड़ जैसा दृढ़ संकल्प था। वे पहाड़ों में जन्में तथा पहाड़ों के लिए जिये।

–विनोद भारद्वाज

डॉ. परमार जयन्ती (4 अगस्त) पर

प्रथम नवम्बर, 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के हिमाचल में विलय के अवसर पर डॉ. परमार ने कहा था, 'आज एक मुद्दत से पिछड़े लोग आपस में मिल रहे हैं। हिमाचलवासियों के लिए स्वतन्त्रता संग्राम का यह चरण भी पूर्ण हुआ। हमारा आज का मिलन हमारी भाषा और अद्वितीय संस्कृति के आधार पर संभव हो सका। ...हिमालय के इस शस्य श्यामल भू-भाग को, जिस पर प्रकृति ने अपना पूरा प्यार उड़ेल रखा है और अपनी सारी सुन्दरता न्योछावर कर रखी है। नये हिमाचल का सूत्रपात सब पहाड़ी निवासियों को सुख समृद्धि एवं आत्म-सम्मान से विभूषित कर भारतीय जन समाज में बराबरी का दर्जा देगा, तब इन पहाड़ों का नाम ऊंचा होगा।'

जन संसद जन संसद जन संसद

कब भरेंगे रिक्त पद

गिरिराज के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा दाना-घाटों के समस्त निवासी शिक्षा मंत्री से अनुरोध करते हैं कि हाई स्कूल घाटों, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर में अध्यापकों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएं।

ज्ञात रहे कि इस पाठशाला में अभी तक मुख्याध्यापक, लिपिक वर्ग समेत कला स्नातक के दो पद, टीजीटी मेडिकल का एक पद, टीजीटी नॉन मेडिकल का एक पद तथा भाषा अध्यापक का एक पद रिक्त पड़ा हैं इस समय पाठशाला में दो सौ के करीब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिनका भविष्य शिक्षकों के अभाव में अंधकारमय है।

अत: हम सरकार से रिक्त पदों को भरने का आग्रह करते हैं।

समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत दाना-घाटों, जिला सिरमौर।

विद्यालय की सुध लें

मैं गिरिराज के माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पाहल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस स्कूल का एक भवन ग्रामीण जनता के सहयोग से बच्चों को शिक्षित करवाने हेतु निर्मित करवाया गया था। परन्तु आज यह भवन जीर्ण शीर्ण हालत में है। भवन की छत एवं दीवारें गिरने की कगार पर है। बच्चों के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। स्कूल भवन की खस्ता हालत के चलते शिक्षक, अभिभावक एवं बच्चे परेशान हैं।

अत: शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि स्कूल भवन की मरम्मत करवाने की कृपा करें जिससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई असुविधा न हो।

सुन्नी शिमला खेमचन्द कश्यप

गरीब परिवारों के लिए वरदान

स्वास्थ्य बीमा योजना

हिमाचल प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना सहायक बनी है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को अब अच्छे इलाज की चिंता नहीं सताती है। वर्ष 2008-09 में इसे शिमला तथा कांगड़ा जिलों में आरम्भ किया गया।

आरम्भ के प्रथम वर्ष में ही एक लाख से अधिक परिवारों को बीमा छत्र प्रदान किया गया। इस योजना की सफलता को देखते हुए इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को वर्ष 2009-10 से प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी लागू कर दिया गया जिससे 2,98,291 बी.पी.एल परिवार लाभान्वित होंगे।

स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के अतिरिक्त जन स्वास्थ्य प्रणाली का सुधार करना है। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना समिति द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसे इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

इस योजना के तहत लाभार्थी को 30,000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के लिए परिवार चलायमान आधार पर बीमा किया जाएगा। बी.पी. एल. परिवार इकाई में अधिकतम 5 सदस्य होंगे तथा इसमें अतिरिक्त आयु सीमा की शर्त नहीं होगी।

बी.पी.एल परिवार को कोई बीमा प्रीमियम नहीं देना होगा तथा उन्हें केवल 30 रुपये वार्षिक पंजीकरण शुल्क ही देना होगा। प्रत्येक लाभार्थी को 60 रुपये मूल्य का स्मार्ट कार्ड नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। बीमा राशि का भुगतान केवल उसी स्थिति में किया जाएगा जब लाभार्थी का राज्य सरकार द्वारा सूचिबद्ध अस्पताल में दाखिल होने पर उपचार किया जाएगा। इस योजना के तहत बीमा पैकेज में लाभार्थी को सभी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नि:शुल्क बीमा छत्र प्रदान किया जाएगा।

अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शिमला तथा कांगड़ा ज़िला के 1,00547 परिवारों को लाया गया है। बीमा छत्र प्रदान करने वाली न्यू इंडिया इंश्युरेंस कम्पनी में बीमा धारकों को 80,242 स्मार्ट कार्ड प्रदान किए हैं जिसमें से 54511 कार्ड कांगड़ा तथा 25731 कार्ड शिमला ज़िला में प्रदान किए गए हैं। अभी तक 310 बी.पी. एल रोगियों को बीमा योजना के तहत उपचार मिला है जिसमें से 82 रोगी शिमला तथा 228 रोगी कांगड़ा ज़िला से हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अधिकांश बीमारियों तथा अस्पताल व्यय को शामिल किया गया है। अस्पताल में दाखिले से पूर्व तथा बाद के व्यय को भी इसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया हैं योजना में शल्य चिकित्सा के उपचार के व्यय को शामिल करने के अतिरिक्त पूर्व के रोगों का उपचार शामिल किया गया हैं इस योजना के तहत रोगी को अस्पताल तक पहुंचने का परिवहन व्यय भी शामिल किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति दौरा 100 रुपये तथा कुल एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में इस योजना को भारत सरकार के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार प्रति बी.पी. एल.परिवार प्रति वर्ष 491,13 रुपये व्यय करगी, जबकि राज्य सरकार की भागीदारी 143.70 रुपये प्रति बी.पी.एल परिवार प्रति वर्ष होगी। प्रदेश के सभी 12 ज़िलों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए लभभग 19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं

बी.पी.एल. परिवारों को और अधिक लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने नई योजना के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं। योजना के तहत बीमित लाभार्थियों को गंभीर बीमारी की स्थिति में उपचार के लिए एक लाख रुपये तक का अतिरिक्त बीमा लाभ प्रदान करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त हृदय रोग, प्रत्यारोपण एवं स्पाइनल सर्जरी तथ न्यूरो-सर्जरी के अस्पताल खर्चे को वहन करने के लिए बीमा लाभ प्रदान करना भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त योजना में पात्र बी.पी.एल परिवारों की महिलाओं को 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त प्रसूति व्यय भी प्रदान करने का प्रस्ताव है जिनमें सामान्य अथवा आप्रेशन द्वारा प्रसूति दोनों ही स्थिति को शामिल करने का प्रस्ताव है।

सूजसवि

कल्याण योजनाओं ने बढ़ाया मदद का हाथ

प्रदेश सरकार पिछड़े एवं कमजोर, गरीब व बेसहारा लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

मण्डी जिला में इस वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 26.87 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत गत वर्ष जिला में 20 करोड़ 51 लाख रुपये खर्च करके 54,510 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। इनमें से 35204 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 14241 महिलाओं को विधवा पेंशन, 4841 व्यक्तियों को अपंग राहत भत्ता और 224 कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता प्रदान किया गया।

गरीबों व पिछड़े वर्गों के लोगों को आवास सुविधा मुहैया करवाने के लिए गृह अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 934 निर्धन व्यक्तियों को नये घरों के निर्माण तथा मकान मुरम्मत हेतु लगभग दो करोड़ रुपये प्रदान किये जबकि अनुवर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत इन वर्गों के 641 पात्र व्यक्तियों को जिनमें 592 व्यक्ति अनुसूचित जाति के सम्मिलित हैं, को 6 लाख 53 हजार रुपये की राशि अथवा कारोबार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

● दया राम शर्मा

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति अपने को निर्बल न समझे इसलिए ऐसे व्यक्तियों से विवाह करने वाली महिला व पुरुष को सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में आठ व पन्द्रह हजार रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्राप्त की जाती है। यदि व्यक्ति की अपंगता 40 से 74 प्रतिशत तक है तो उस मामले में उससे विवाह करने वाले व्यक्ति को आठ हजार और यदि व्यक्ति को अपंगता 75 से 100 प्रतिशत है तो ऐसे व्यक्ति से विवाह करने वाले महिला अथवा पुरुष को 15 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत जिला में 42 पात्र व्यक्तियों को तीन लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। समाज में महिलाओं के जीवन स्तर के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं जिसमें बाल विधवा पुनर्वास योजना भी शामिल है।

ऐसी बस्तियां जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवारों की संख्या 25 है अथवा 5 से 10 तक घर है, उन बस्तियों में पक्की गलियों का निर्माण, वातावरण सुधार, कुएं, बावड़ी अथवा लघु पेयजल योजनाओं का निर्माण आदि कार्य उन बस्तियों के सुधार के लिए किये जाते हैं। जिला में 200 हरिजन बस्तियों के सुधार पर पिछले वर्ष एक करोड़ 40 लाख रुपये व्यय किये गये। सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को पहली से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति एवं शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत स्वरोजगार अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जिला में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 590 विकालंग विद्यार्थियों को दस लाख रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई और 50 अपंग व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए एक लाख 25 हजार रुपये की राशि सहायता के रूप में प्रदान की गई।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निसहाय महिला के 14 वर्ष की आयु से कम के दो बच्चों के पालन- पोषण हेतु एक हजार रुपये प्रति बच्चा वार्षिक दर से सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस महत्वकांक्षी मदर टेरेसा मातृ संबल योजना के तहत जिले में 4901 महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया गया तथा योजना के तहत 22.43 लाख रुपये खर्च किये गये। अनुसूचित जाति के युवाओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिले में पिछले वर्ष 9 लाख रुपये खर्च करके 58 युवाओं को लाभान्वित किया गया जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के 8 युवाओं को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की गई जिस पर एक लाख 70 हजार रुपये खर्च किये गये।

बालिकाओं एवं महिलाओं का सर्वांगीण विकास हुआ सुनिश्चित

कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर उपमण्डल के अंतर्गत लम्बागांव में कार्यान्वित बाल विकास परियोजना, केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित समेकित विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत 270 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शिशुओं, किशोरियों, दूध पिलाने वाली माताओं तथा गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार, पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच तथा टीकाकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभा रही है।

विकास खण्ड लम्बागांव में 6 माह से 6 वर्ष तक के 5185 बच्चों, 1288 गर्भवती/धात्री माताओं तथा 1507 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली किशोरियों को ग्रामीण स्तर पर 270 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इसके अलावा बालिकाओं और महिलाओं को आर्थिक आधार पर सुदृढ़ करने व उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी क्रियान्वित की गई हैं।

किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत लड़कियों को स्वरोजगार अपनाने व उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए वर्ष 2008-09 में 20 किशोरी लड़कियों को खिलौने बनाने तथा 20 किशोरी लड़कियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिस पर 53,000 रुपये खर्च किये गये।

पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 11-15 वर्ष व 15-18 वर्ष की किशोरियों को जिनका वजन 30 से 35 किलोग्राम से कम हो, का कुपोषण दूर करने के लिए प्रति किशोरी 6 किलोग्राम गेहूं/चावल उपलब्ध करवाया जाता है। प्रत्येक तिमाही में किशोरी के वजन में वृद्धि/कमी की जांच वजन लेकर की जाती है। वर्ष 2008-09 में 2044 किशोरियों को 935.44 क्विंटल गेहूं आवंटित किया गया।

सुरेश कटोच

लम्बागांव क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह योजना के तहत 284 समूहों का गठन किया गया जिनमें 3861 महिला सदस्य हैं। इन समूहों की बचत 25,42,405 रुपये है व ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु बैंकों से 14,31,000 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली गई है। स्वयं सिद्धा योजना भी महिलाओं के उत्थान व उन्हें आत्म निर्भर बनाने में कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिनमें 1621 महिला सदस्य हैं। इन स्वयं सहायता समूहों की कुल बचत 17,61,567 रुपये तथा सभी समूह बैंकों से सम्बद्ध है। इन समूहों द्वारा अपने काम-धंधे शुरू करने के लिए बैंकों से 9,25,000 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली गई है।

विद्युत जिला बनने की ओर अग्रसर चम्बा जिला

हिमाचल प्रदेश देश का ऊर्जा राज्य बनने की ओर निरन्तर अग्रसर है। इसके लिए सरकारी व संयुक्त तथा निजी क्षेत्र में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसी कड़ी में चम्बा जिला भी विद्युत जिला बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। चम्बा जिला के उपमण्डल भरमौर में खड़ामुख के पास रावी के दायीं ओर से मिलने वाले सहायक बुधिल नाले में निर्माणाधीन 70 मेगावाट जल विद्युत परियोजना एक है जिसका कार्य निष्पादन निजी क्षेत्र में किया जा रहा है। इस जल विद्युत परियोजना का कार्य लैकोग्रीन पॉवर द्वारा किया जा रहा है। चम्बा जिला में इस समय लगभग 7-8 जल विद्युत परियोजनाएं चिन्हित की जा चुकी हैं, जिसमें अधिकांश जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है और कुछ पर शुरूआती तौर पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

चमेरा चरण-3, 231 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का कार्य एनएचपीसी जोकि भारत सरकार का उपक्रम है, किया जा रहा है। 70 मेगावाट बुधिल पन बिजली परियोजना लैकोग्रीन व कोस्टल कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह भरमौर क्षेत्र में 3 मेगावाट होली, 250 मेगावाट कुठेड़, 2 मेगावाट स्यूर, 5 मेगावाट हड़सर, 2 मेगावाट लूणा व 250 मेगावाट कुलेठ जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमण्डल में कार्यान्वित की जानी है। इन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो जाने पर चम्बा जिला विद्युत जिले के नाम से जाना जायेगा।

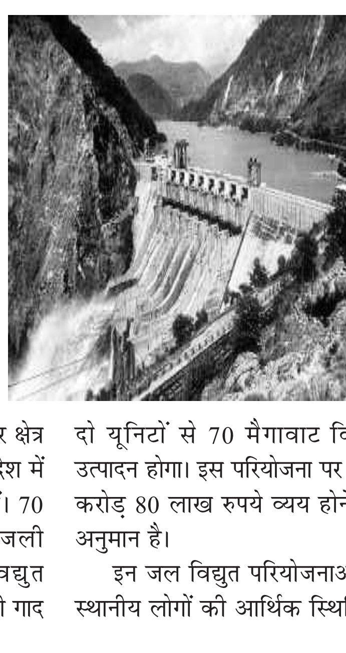

चम्बा में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना 540 मेगावाट चमेरा प्रथम है। चमेरा दो 300 मेगावाट, चमेरा-3 231 मेगावाट, बैरास्यूल परियोजना 180 मेगावाट इसी तरह चम्बा जिला में छोटी-छोटी कई पन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। रावी नदी के क्षेत्र में व अन्य सहायक नालों पर कम से कम 2100 मेगावाट विद्युत क्षमता है। चम्बा जिला के भरमौर क्षेत्र में बनने वाली यह परियोजनाएं देश में अपनी तरह की परियोजनाएं हैं। 70 मेगावाट की बुधिल पन बिजली लैकोग्रीन पॉवर गृह द्वारा विद्युत उत्पादन के उपरांत निकलने वाली गाद रहित जल का उपयोग होगा। जल को रोकने के लिए बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिसका स्तर से 58 मीटर ऊंचा कंकरीट ग्रैविटी का बांध होगा। इस परियोजना में 35-35 मेगावाट के दो यूनिटों से 70 मैगावाट विद्युत उत्पादन होगा। इस परियोजना पर 418 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

इन जल विद्युत परियोजनाओं से स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। प्रमाणित व्यक्तियों को घास, फसल, मकान, वृक्ष इत्यादि की क्षतिपूर्ति के रूप में बुधिल पन बिजली परियोजना की ओर से 9 प्रभावित पंचायतों को 90 लाख रुपये विकास के लिए दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के विकास पर 630 लाख रुपये व्यय करने का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा वनीकरण, चारागाह विकास अल्प हित चारागाह विकास, भूमि कटाव, नदी किनारों की मजबूती, वनौषधियों का विकास, वन्य प्राणी विकास, भूमि व जल संरक्षण कार्य निष्पादन के लिए आधारभूत संरचना आदि पर 435.27 लाख रुपये परियोजना द्वारा व्यय करने का प्रावधान है। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक आर्थिक लाभ के साथ-साथ सड़कों में सुधार व दूरसंचार व्यवस्था में सुधार आयेगा।

–केहर सिंह ठाकुर

कृपया
पृष्ठ 6-7 के लिए
सेंटरस्प्रेड देखें

न धनपतराय-न नवाबराय
बस प्रेम चन्द होकर जिए कथा सम्राट

सच्चा साहित्यकार साहित्य की (रूह) आत्मा को पहचानता है। उसका समूचा रचना संसार इसी पहचान परख के बूते पर फलता फूलता और फैलता है। वह बहुधा अपने देशकाल से प्रभावित होता है। मुन्शी प्रेम चन्द ने साहित्य के विषय में निज विचार व्यक्त करते हुए एक जगह स्पष्ट करना चाहा है-'साहित्य का आधार जीवन है। इसी आधार पर जीवन की नींव खड़ी होती है। उसकी अटारियां, मीनारें एवं गुंबद बनते हैं। हां, उसकी बुनियाद मिट्‌टी के नीचे दबी पड़ी होती है...जिसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा। और जीवन ईश्वर की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। पर साहित्य आदमी की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है...।'

जरा गौर फरमाएं, आज से एक सौ अठाईस वर्ष पूर्व जिस विभूति ने इस देश के एक मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में जन्म लिया...प्रसन्नचित्त पिता ने नवागत जातक को धनपतराय नाम दिया और अति भावविभोर एवं खुश ताया ने उसे नवाब राय कहकर पुकारा। मगर परिस्थिति की विडम्बना या भाग्य का क्रूर व्यंग्य तो देखे कि आजीविका के लिए बड़े होने पर यही धनपत राय अंग्रेज सरकार के मामूली कर्मचारी बने...एक स्कूल मास्टर। उन्हीं दिनों प्रेम चन्द की कहानियों का पहला संग्रह 'सोजे-ए-वतन' के नाम से प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी हाकिमों को इन कहानियों से बगावती बारूद की गंध आने लगी। पुस्तक पर प्रतिबंध लगा...बाद में पता चला कि सोज-ए-वतन का लेखक सरकार का अपना कर्मचारी धनपतराय है। मास्टर की खिंचाई की गई...। मेहरबानी का व्यवहार दर्शाते हुए अधिकारियों ने नौकरी से नहीं निकाला, आगे के लिए, अलबत्ता चेतावनी जरूर दी कि अब जो लिखो तो छपवाने से पूर्व कलेक्टर साहिब की स्वीकृति अवश्य प्राप्त करो। मगर लिखना प्रेम चन्द का नित्य प्रति का अनिवार्य कर्म था। ऐसे में रोज रोज साहिब के दफ्तर के चक्कर कौन काटे? उन्होंने अपने वजूद से नवाब का तगमा (नाम) हटा दिया। अब वे धनपत राय रह गये थे। पर धन के पति अब भी कहां थे। ऐसे में जब वे कुंठित और दुखी अनुभव कर रहे थे, उनकी भेंट मुंशी दया नारायण निगम से हो गई। उन्होंने धनपतराय को एक नया नाम सुझाया, अब तुम प्रेम चन्द नाम से लेखन करो।

मुंशी जी एक दम प्रसन्न हो गये। सन् 1910 में इसी नाम से उनकी पहली कहानी 'बड़े घर की बेटी' छपी। उसके पश्चात मुंशी जी बराबर इसी नाम से लिखते रहे। अब वे दोनों भाषाओं उर्दू तथा हिंदी में छपने लगे। फिर पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी ओर नमक का दरोगा आदि दूसरी कहानियों में भी तत्कालीन सामाजिक स्थिति को बड़े मार्मिक अंदाज में उन्होंने व्यक्त किया।

समाज के हाशिये पर पड़े हुए दलित लोगों की सुध ली

प्रेम चन्द जी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में ऐसे पात्रों का सृजन किया जो पाठकों को महसूस हुआ, लेखक ने समाज में हाशिये पर खड़े हुए लोगों को केन्द्रीय धरातल प्रदान किया है। वे एक किसान जीवन के गाथाकार के रूप में हमारे सामने आये। किसान की गाथा के बहाने प्रेम चन्द अन्य वर्गों को भी उसी में समेटते हैं। यहां आपको किसान मिलेंगे, मजदूर भी मिलेंगे, पिछड़ा वर्ग के दलित जन मिलेंगे। यही नहीं प्रेम चन्द ने अनेकों अनबोलता यानी मूक वर्गों को भी वाणी दी। दलित प्रसंग उनके प्रमुख सरोकारों में था। आज माना कि कितने ही तथाकथित दलित लेखक बहुत सारे लेखन को सहानुभूति का साहित्य कहकर खारिज कर रहे हैं, तथापि उनका जोर तो दलित स्वाभिमान वाले लेखक पर है। बरअक्स इसके प्रेम चन्द जी का साहित्य दलित वर्ग को

● प्रेम पखरोलवी

संपूर्ण तसवीर पेश करने वाला साहित्य है।

प्रेमचन्द की उपेक्षा कैसे और क्यों?

बीसवीं सदी के दूसरे दशक में जब कांग्रेस (1921 ई.) औपनिवेशक स्वराज्य की मांग कर रही थी, प्रेम चन्द जी ने लिखा था, 'भारत के उद्दार का कोई उपाय है, तो वह स्वराज्य है, जिसका मतलब है-मन और वचन की पूर्ण स्वाधीनता। है व आदर्श विरोध का प्रत्याया वे सही मायनों में गांधीवादी विचारधारा पर न केवल विश्वास ले आये थे, वरन सक्रिय रूप से उसे निज लेखन में ढाल भी रहे थे। राजनीतिक चेतना से सम्पन्न प्रेम चन्द ने स्पष्ट कहा था, 'साहित्यकार का लक्ष्य महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है-उसका दरजा इतना न गिराइये। और साहित्यकार देश भक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली निरी सच्चाई ही नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। (द्रष्टव्य साहित्य का उद्देश्य)।

कथा यात्रा रोचक आरम्भ

प्रेम चन्द जी ने अपनी कथा यात्रा की शुरूआत एक दलित प्रसंग से की और अंत भी। 'मेरी पहली रचना' नामक कहानी में वे अपने दूर के मामा का मजाक उड़ाते हैं...मामा का एक दलित युवती से सम्बन्ध था। दलितों ने उनके (मामा के) घर में घुसकर पिटाई की थी। फिर उनकी अंतिम महत्वपूर्ण कहानी 'कफन' भी दलित जीवन से सम्बन्धित है। इस पूरी यात्रा के बीच में उनके यहां कितने ही दलित पात्र चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। 'गुल्ली डंडाक गया हो', 'दूध का दाम' का मंगल या ठाकुर का कुआं की गंगी हो...सदगति का दुखी या फिर रंग भूमि का सूरदास दलित जीवन की त्रासदी उसमें अंतर्निहित श्रेष्ठ मानवीय गुण और सूखी लकड़ी में जैसे आग रहती है, वैसी ही संघर्ष चेतना प्रेम चन्द को दिखाई देती है।

सन् 1936 में प्रकाशित हुई थी 'कफन' कहानी। उस समय प्रेम चन्द अपने वैचारिक और कलात्मक उत्कर्ष (शीर्ष) पर पहुंच चुके थे। आम आदमी का शोषण और अपमान उनकी आंखों के सामने था...वर्ग संघर्ष भी वे देख चुके थे...असल में वे ऐसे चरित्रों की रचना कर रहे थे जो निज आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों के लिए मुखर बनते। कफन कहानी के दलित पात्र घीसू और माधव कैसे पात्र हैं? स्तब्ध तथा विजड़ित संवेदना के कामचोर पात्र। इनमें यथार्थ की कुरुपताएं भरी हुई हैं। उनके अवचेतन मन की टोह ली जाये तो पायेंगे कि वहां गहरी विद्रोह भावना भरी हुई है। कफन का पैसा लेकर शराबखाने में जा घुसना धार्मिक पाखण्डों का मुंह चिढ़ाना नहीं तो क्या है? दूसरी तरफ सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का प्रतिकार भी इसमें निहित है। यह एक जमीनी सच्चाई है कि समाज के मोटे मोटे लोग गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और निज पापों को धोने हेतु गंगा नहाते हैं। ठगिनी क्यों नैना झमकावै, गाते हुए जब गिर पड़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें अपनी बहू-बीबी बुधिया से मलतब नहीं था। उनके पीने नाचने उछलने में आखिर यही तो उभरता है कि वे दोनों बुधिया को कितना प्यार करते थे। जीने को उनमें बड़ी भूख थी, मगर वे सामाजिक विषमता की चपेट में फंसे हुए थे। व्यवस्था ने अपना क्रूरतम रूप दिखाकर उनका अमानवीयकरण कर दिया था।

कफन-एक औपचारिक महाकाव्य है

इस दृष्टि से 'कफन' कहानी भारतीय निम्न वर्ग का औपन्यासिक महाकाव्य कहा जा सकता है। कहानी का एक शब्द गद्य होते हुए भी कविता को समान गहरे संवेदनों, व्यंग्यार्थ और कलात्मक सौंदर्य को सामने लाता है।

कुछ आलोचक कफन को डिह्यूमनाईजेशन वाली कहानी बतलाते हैं...उनका मानना है कि प्रेम चन्द दिखाना यही चाहते हैं कि घीसू और माधव जिस व्यवस्था के उत्पाद हैं, वह कितनी गर्हित, कितनी घटिया व्यवस्था है। इसमें एक अंतर्निहित संदेश है कि ऐसी व्यवस्था को बने रहने का कहीं कोई हक नहीं है-उसे बदल देना चाहिए।

रंगभूमि का सूरदास-संघर्षशील योद्धा है

उधर रंगभूमि (उपन्यास) का नायक सूरदास भी दलित वर्ग (चमार जाति) का प्रतिनिधित्व करता है। वह न केवल दलितों की नुमांयदगी करता है वरन वह बार-बार हार जाने पर भी लड़ने के लिए कमर कसता है। पूंजीवादी ताकतें उसे मिटाना चाहती हैं। लील जाना चाहती हैं उसकी भूमि को। मगर वह पीछे नहीं हटता। आखिर वह जमीन हड़प ली जाती है। वह साम्राज्यवादियों को ललकार कर सुनाता है-

...तुम (लोग) मंजे हुए खिलाड़ी हो...दम नहीं उखड़ता तुम्हारा। मिलजुलकर खेलते हो-उत्साह भी खूब हैं हमारा दम उखड़ जाता है। हम खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते आपस में झगड़ते हैं...कोई किसी की नहीं मानता...और तुम खेल में निपुण हो- हम अनाड़ी हैं।

परेशानी का चोला

हर तरफ इनसान ने ओढ़ रखा है,
परेशानी का चोला,
फंसा हुआ है हर युवक हर बच्चा,
परेशानी के जाल में,
हर तरफ ओढ़ रखा है,
परेशानी का चोला।
हर तरफ है परेशानी का आलम,
हर तरफ है उलझने,
कुछ खो चुके हैं सुख और चैन अपना,
कुछ हो गये बीमार,
हर तरफ है परेशानी का आलम।
छोड़ दे परेशानी का चोला,
ओढ़ ले खुशी का चोला,
जिंदगी है चार दिन की जी ले खुशी से,
छोड़ इस परेशानी के झमले को।
जीवन बना दे अपना मधुर,
छोड़ कर इस परेशानी से झोले को।

–भूपेन्द्र शर्मा

क्या आप जानते हैं?

जैतून के तेल और हल्दी के रोगनाशक गुणों पर नई खोज

भारतीय मानस में हल्दी सदियों से पवित्र मानी जाती है और धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका उपयोग होता है। इसके औषधीय गुणों का पता भी बहुत पहले लग चुका था। संभवतः, इसीलिए गंभीर चोट लगने पर हल्दी–दूध दिये जाने की परम्परा रही है। आधुनिक युग में विज्ञान भी हल्दी के चमत्कारी गुणों से चकित है। वैज्ञानिकों ने इसके प्रमुख तत्व करक्यूमिन का पता पहले ही लगा लिया था, लेकिन घाव को भरने में करक्यूमिन किस प्रकार काम करता है, यह किसी को मालूम नहीं था? अमरीका के मिशिगन के वैज्ञानिकों ने नवीनतम शोध में यह रहस्य भी जान लिया है। करक्यूमिन की कार्य प्रणाली को जानने के लिए एक उच्च तकनीक उपकरण सॉलिड स्टेट एनएमआर 'स्पेक्ट्रोस्कोपी' का प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि करक्यूमिन के अणु पूर्णतः जैव रसायन की तरह काम करते हैं। इसके अणु क्षतिग्रस्त कोशिका में समाविष्ट होकर उसकी दीवारों को मजबूत और व्यवस्थित बनाते हैं। यह कोशिका को संक्रामक जीवाणुओं का सामना करने में सक्षम बनाता है। पुर्तगाल के पोर्टो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जैतून के तेल में हृदय रोगों और दिल के दौरों से बचाने वाले तत्व का पता लगाया है। शोध दल के अनुसार जैतून के तेल में डीएचपीईए–ईडीए' एंटी ऑक्सीडेंट होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। शोध के अनुसार जैतून के तेल का आहार में उपयोग करने वाले लोगों का अच्छा स्वास्थ्य इसका उदाहरण है।

1. वह देश जिसकी धरती पर भारत ने उसी को हराकर कोई क्रिकेट शृंखला मार्च– अप्रैल 2009 में जीती?
2. भारत की वह शेरनी जो लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम शेरनी है?
3. 1857 में किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी?
4. 'सत्यार्थ प्रकाश' की रचना किसने की थी?
5. भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से सम्बन्धित है?
6. शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग का खतरा होता है?
7. भारत का कौन सा शहर 'सनसिटी' के नाम से विख्यात है?
8. भारत का परमाणु करार सबसे पहले किस देश के साथ हुआ?
9. भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा है?
10. सिविल सेवाएं भारतीयों के लिए कब प्रारम्भ की गई?
11. सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने जारी किया?
12. सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस जगह प्रवेश करती है?
13. प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है?
14. 'पहाड़ बेगाने नहीं होंगे' पुस्तक के लेखक कौन हैं?
15. हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी शिल्ला (7025 मीटर) किस पर्वत शृंखला में है

प्रस्तुति–नर्बदा कंवर

□□□

उत्तर-1. न्यूजीलैंड, 2. मझली (रणथम्भौर नेशनल पार्क में 1997 में जन्मी शेरनी को 'ट्रू ऑपरेटर्स फॉर टाइगर्स' TOFT संगठन द्वारा प्रारम्भ किया गया वह लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड इस वर्ष अप्रैल में प्रदान किया गया), 3. मंगल पाण्डे को, 4. स्वामी दयानन्द सरस्वती, 5. जम्मू–कश्मीर से, 6. कॉलेस्ट्रॉल, 7. जोधपुर, 8. फ्रांस के साथ, 9. भारत रत्न, 10. 1853 ई. में, 11. शेरशाह ने, 12. शिपकी (जिला किन्नौर), 13. 3,978 मीटर, 14. श्री शांता कुमार, 15. जसकर पर्वत शृंखला में।

लघुकथा

गुरु दर्शन

सवारियों से लबालब भरी बस तेजी से राजमार्ग पर दौड़ रही थी। बस में ज्यादातर लोग एक विशेष स्थान की ओर जा रहे थे जहां उनके धार्मिक गुरु का प्रवचन था। ये लोग भजन कीर्तन करते जा रहे थे। सारा वातावरण भक्तिमय था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो यह इंसानियत की व अध्यात्मक वातावरण की चरम सीमा हो।

जलपान के लिए थोड़ी देर बस रूकी तत्पश्चात धीरे-धीरे बस आगे बढ़नी शुरू हुई। एक स्त्री जो कि भजन मण्डली में सम्मिलित थी, दौड़ी-दौड़ी बस के समीप पहुंचने पर जल्दी से बस पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। वह बस की स्पीड से तालमेल न बैठा सकी और बस से गिरकर चोटिल हो गई। उसे हस्पताल पहुंचाना आवश्यक था। कुछ लोगों ने बस को रोकने का प्रयास किया परन्तु धार्मिक आस्था वाले लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया कि हम लेट हो गये तो गुरु जी के दर्शन नहीं कर पायेंगे और न ही उनका प्रवचन सुन पायेंगे। बस चल पड़ी। महिला कहराती रही व सहायता के लिये पुकारती रही।

कुछ समय बाद एक कार सामने से आई व उस घायल महिला को देखकर रुक गई। कार सवार ने महिला को अपनी कार में बिठाते हुए कहा कि बहन घबराओ मत मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा देता हूं। इससे पहले कि कार चलती मैंने कार चालक से पूछा भाई साहब क्या आपके कोई गुरु नहीं है? उन्होंने मुस्कुराते हुए अंदाज में उत्तर दिया, नहीं और कार अस्पताल की ओर चल दी।

डॉ. राजेन्द्र सिंह ठाकुर

नवोदित कलम

युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति

स्वास्थ्य अमूल्य धन है और जीवन का मूल भी। लेकिन इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। प्रकृति मानव को स्वस्थ अवस्था में पैदा करती है। मनुष्य की चंद भूलें उसे अच्छे स्वास्थ्य का मोहताज बना डालती है। इन्हीं भूलों में एक भयंकर भूल समाज में बढ़ते नशे की आदत भी है। विशेषत: आज का युवावर्ग इस दल-दल में बुरी तरह से फंसता जा रहा है। पहले फैशन के लिए नशा और फिर यही फैशन शरीर के लिए मजबूरी बन जाता है। परिणामस्वरूप जिन कंधों को देश, समाज और परिवार के दायित्वों को निभाने में फैलादी होना चाहिए था। आज वही कंधे अशक्त और जर्जर होने लगे हैं।

मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से बेखबर युवक पहले तो जिज्ञासावश ऐसा करते हैं। परन्तु धीरे-धीरे वे इस जाल में इस तरह फंस जाते हैं कि वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ समय के लिए ये मादक पदार्थ व्यक्ति के मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ा तो देते हैं। लेकिन बाद में धीरे-धीरे क्षमता घटने का क्रम शुरू होता है। अंत में शरीर की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए नशा विवशता का रूप धारण कर लेता है और नशा न करने की स्थिति में आदमी सामान्य कामकाज करने में भी असमर्थ हो जाता है।

नशे का आदी होने का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसका सेवन करने वाले को हर बार पहले से अधिक खुराक की जरूरत पड़ जाती है। इसे नशा सहनशीलता कहते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब नशा उसके आय के साधनों की पहुंच से परे हो जाता है। फिर शुरू हो जाता है उसका नैतिक पतन। आदी हो जाने के बाद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह कोई भी गैर कानूनी काम कर सकता है।

मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से बेखबर युवक पहले तो जिज्ञासावश ऐसा करते हैं। परन्तु धीरे-धीरे वे इस जाल में इस तरह फंस जाते हैं कि वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ समय के लिए ये मादक पदार्थ व्यक्ति के मस्तिष्क की कार्य क्षमता को तो बढ़ा देते हैं लेकिन बाद में धीरे-धीरे क्षमता घटने का क्रम शुरू होता है।

आखिर आज समाज में नशे का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है। क्यों भटक गया है हमारा युवा वर्ग? कितनी दुखद विडम्बना है। क्या भौतिकवाद की अंधी दौड़ में भागते-हांफते अभिभावकों के पास अपने बच्चों को सही मार्ग दर्शन व अच्छे संस्कार देने का समय नहीं? बच्चों को बुरी आदतों के चंगुल में फसाने के लिए कौन जिम्मेवार है। अभिभावकों के पास अपने बच्चों को पैसा तो देने को है परन्तु समय नहीं।

समाज में कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा मादक पदार्थों का व्यापार करके रातों-रात अमीर बनने का सपना देखना भी बढ़ते नशे की आदतों के लिए जिम्मेदार है। ऐसे लालची लोगों को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए। शायद युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी भी नशे का एक कारण है। आज बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा बड़ी आसानी से नशे के चंगुल में फंस रहे हैं। राजस्व प्राप्ति के लालच में एक तरफ मादक पदार्थों के उत्पादन में चुपके-चुपके प्रोत्साहन दिया जाता है वही दूसरी ओर इनके प्रचलन के दुष्परिणामों पर घड़ियाली आंसू बहाये जाते हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति युवा वर्ग पर निर्भर करती है। देश को खुशहाल बनाने के लिए सर्वप्रथम युवाओं में आये भटकाव को रोकना अत्यंत जरूरी है। युवाओं को समय से पहले बूढ़ा एवं अपाहिज बना देने वाले मादक पदार्थों से दूर रखना सरकारी तंत्र के साथ हर मनुष्य का सामूहिक दायित्व बन जाता है।

स्वास्थ्य रूपी अमूल्य रत्न खोकर पुन: प्राप्त करना कठिन है। अत: प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। महाप्रज्ञ विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा था, 'मनुष्य को सौ वर्ष आयु वाला बताया है फिर वह क्यों पूर्ण आयु नहीं पाता?' तब विदुर ने कहा था, 'महाराज मनुष्य की आयु को क्षीण करने वाले उसके संस्कार, स्वभाव और चिंता है।'

मानव का उत्कर्ष केवल धन और बल से संभव नहीं। इसके लिए उसे आत्मावलंबी बनना जरूरी है। यदि हर व्यक्ति का बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना है तो युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना जरूरी है जिससे राष्ट्र भी सशक्त होगा।

—अति देवी,
कक्षा नवम्

बाल कविता

जय बोलो हिन्दुस्तान की

हिंसा विघटन जहां पनपते
करते दुर्बल देश महान,
दुर्बल राष्ट्र नहीं पा सकता
दुनिया में कोई सम्मान।
रहकर एक देश रक्षा में
लगा दो बाजी जान की।
जय बोलो हिन्दुस्तान की।
जड़ें काटकर वैमनस्य की
बीज शांति का बोना है,
भाईचारे के धागे में
मानव पुष्प पिरोना है।
सीख यही गुरुग्रंथ, बाइबिल
गीता और कुरान की
जय बोलो हिन्दुस्तान की।
आजादी के लिए शहीदों-
ने भी अनगिनत त्रास सहे,
इसकी रक्षा करनी है अब
जब तक अंतिम सांस रहे।
कसम हमें है उन्हीं शहीदों-
के पावन बलिदान की।
जय बोलो हिन्दुस्तान की।

▶▶उमाशंकर यादव

लघुकथा

दायित्व

अकस्मात विवाहोत्सव में खामोशी पसर गई। लोग हड़बड़ाहट में गली की ओर खुलने वाले मुख्य द्वार की ओर भाग रहे थे। बाहर गली में चीखों के स्वर निरंतर तीव्र हो रहे थे।

गली में जाकर देखा तो लोग वृत्ताकार में खड़े तमाशा देख रहे थे। बीच में औंधे मुंह गिरी अर्द्धनग्न, कृशकाय भिखारिन पर कुछ उदण्ड किशोर बेरहमी से लात-घूंसों के प्रहार कर रहे थे। बेलगाम किशोर बार-बार पूछ रहे थे, 'बता, आज तक कितनी चोरियों की? कहां-कहां की? अगला निशाना कहां है?'

लोगों के मना करने पर युवक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बस एक ही रट कि ये भिखारी चोर होते हैं। दिन को घर-घर का भेद लेते हैं, रात को चारी करते हैं। भीख की आड़ में रात को अंदर घुसने के रास्तों का पता लगाते हैं।

भिखारिन की छाती से चिपका शिशु इस दौरान छिटक कर दूर पड़ा। निरीह भाव से मां की दुर्दशा निहार रहा था। अधिक पिटाई से बीमार सी दिखने वाली भिखारिन इस बीच गश खाकर चित हो गई। मामला संगीन हुआ देख उद्दण्ड किशोर नौ दो ग्यारह हो चुके थे। इसी दौरान कुछ दयावान लोग आगे बढ़े। भिखारिन को होश में लाने के प्रयास में कुछ पुरानी अखबार से हवा दे रहे थे। कुछ पानी की बूंदे मुंह में डालने का प्रयास कर रहे थे। बीच-बीच में बतिया रहे थे, पता नहीं आज के युवाओं को ये क्या हो गया है? जहां देखो हुड़दंग और अनुशासनहीनता। शिक्षा और संस्कार नाम की तो इनमें चीज ही नहीं। खाक सिखाते होंगे इनके शिक्षक इन्हें स्कूल में।

शादी से लौट आया हूं। गली का वह वीभत्स दृश्य बैठे-बैठे आंखों के आगे तैर जाता है। वह ताना भरा स्वर भी-खाक सिखाते होंगे इनके शिक्षक. ..।

सोचता हूं सिखाने का ठेका क्या शिक्षकों ने ही ले रखा है। अभिभावकों का कोई 'दायित्व' नहीं?

—ज्ञान चन्द शर्मा

कराटे के जुनून ने बनाया राष्ट्रीय प्रशिक्षक

किसी भी क्षेत्र में यदि आगे बढ़ने का जुनून हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता है और न ही उम्र उसकी आड़े आती है। यह बात कुमारी संगीता रानी ने सिद्ध कर दी है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सबसे कम उम्र की करोटे कोच कुमारी संगीता रानी विश्व की पहली ऐसी कोच है जिसने बुडापेस्ट हंगरी में शारीरिक शिक्षा व खेल विजन में सामान्य स्थिति कोर्स में प्रथम रैंक कोच का खिताब हासिल किया। यह खिताब उसने 18 मार्च से 10 जून तक चले अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग कोर्स के दौरान हंगरी के बुडापेस्ट में लिया। कुमारी संगीता रानी पुरानी मण्डी से सम्बन्ध रखने वाली मध्यवर्गीय परिवार की होनहार खिलाड़ी है जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी खेल को अपना कैरियर बनाया। युवा कोच कुमारी संगीता रानी का झुकाव आरम्भ से ही खेलों की ओर था।

मण्डी राजकीय महाविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए करने के बाद योग में कलकत्ता से एक वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने बीपीएड की डिग्री भी हासिल की। करोटे में ब्लैक बैल्ट प्राप्त कर बुशू में एक वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया। करोटे में दक्षता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय में बतौर योग शिक्षक व कराटे की कक्षाएं लगाई। उन्होंने पालमपुर विश्वविद्यालय में भी कार्य किया। तदोपरांत कुमारी संगीता सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में राष्ट्रीय कोच के रूप में नियुक्त हुई। वे हिमाचल से एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वुशू खिलाड़ी बनकर देश के 18 खिलाड़ियों के साथ दुनिया के 26 देशों के 46 प्रतिनिधियों में से जनरल कंडीशनिंग पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अन्य कलाओं की भांति खेल को भी एक कला माना है तथा अपनी विधा में दक्षता हासिल की है। हिम्मत और आत्म विश्वास उनमें कूट-कूट कर भरा है तथा उन्होंने हंगरी में आयोजित पाठ्यक्रम में साबित किया और सबसे कम उम्र के बावजूद भी प्रथम स्थान पाया। संगीता के अनुसार सफल प्रशिक्षक वही है जो शून्य से खिलाड़ियों को पदक दिलाने की स्थिति में पहुंचाए। कराटे के अतिरिक्त संगीता हैरतअंगेज कारनामे भी करती है जिसमें पेट के ऊपर से मोटर साइकिल गुजारना, कोहनी से ईंटों को तोड़ना, बर्फ की सिल्ली को तोड़ना इत्यादि शामिल हैं। आज वे प्रदेश की बालिकाओं के लिए एक आदर्श बनी है।

—हेमकांत कात्यायन

प्रेरक प्रसंग

दूसरों के लिए

दक्षिण भारत के स्वनाम धन्य दार्शनिक कवि तिरुवल्लुवर एक दिन सरिता तट पर बैठी थी, अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सरिता में कूदकर अपने प्राण देना चाहता है। तिरुवल्लुर ने दौड़कर उसे पकड़ लिया तो उसने शिकायत की, 'जिस जीवन की कोई सार्थकता न हो, उसकी रक्षा करने से क्या लाभ?' तिरुवल्लुर बोले, 'देखो, इस दुनिया में धूल का एक कण तक निरर्थक नहीं है। अभी तुम्हें अपना जीवन अपने लिए अनुपयोगी लग रहा है, पर निजी उपयोगिता ही तो एकमात्र उपयोगिता नहीं है। अपने लिए नहीं, तो दूसरों के लिए तुम उपयोगी बन सकते हो और जब तुम दूसरों के लिए अपना जीवन बिखेर देंगे तो अपने लिए भी तुम्हारा जीवन उपयोगी सिद्ध होने लगेगा।'

—फेनम सौगानी

पुस्तक प्रेम

'स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।' यह नारा देने वाले महापुरुष का नाम है-बाल गंगाधर तिलक। हां उन्हें पुस्तकों से कितना प्रेम था। इसका एक उदाहरण उनके विवाह के समय की घटना से मिलता है।

एक सादे मंडप में तिलक की शादी हो रही थी। फेरों की रस्म के उपरांत उनके ससुर जी ने उनसे पूछा, 'मेरे दामाद जी। आप दहेज में क्या लेंगे? साइकिल, घड़ी, सोने की चैन या शीशम का संदूक।'

यह सुनकर तिलक मुस्कराये और बोले, 'मुझे इन महंगी वस्तुओं में से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, मैं सोना, साइकिल, घड़ी आदि कुछ नहीं चाहता, हां, अगर आप दहेज में रस्म के मुताबिक कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे शिक्षाप्रद, लाभकारी और उपयोगी पुस्तकें दें जो मेरे अध्यापन तथा जीवन में सहायक हों, जिनके माध्यम से मैं इंसान, समाज, देश और चरित्र को अच्छी तरह समझ सकूं और ऐसा ही उज्ज्वल ज्ञान अपने शिष्यों, परिवार के सदस्यों, समाज और देश को दे सकूं।'

अपने दामाद के मुख से ऐसी बात सुनकर ससुर जी गदगद हो उठे। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू उमड़ आये और उन्होंने अपने दामाद तिलक को 10 शिक्षाप्रद पुस्तकें भेंट (दहेज) में दीं। पुस्तकें पाकर तिलक बड़े प्रसन्न हुए और इन पुस्तकों की बदौलत ही वे देश और समाज की सेवा में तन-मन से जुड़ गये...।

इतिहास में स्वर्ण पन्नों में देश प्रेम तिलक का पुस्तक प्रेम अमर है तथा यह पुस्तक प्रेम हमें जीने की एक नई राह दिखाता है।

—अर्चना सौगानी

कांगड़े दिया वोलिया च

हिल्लण

डॉ. एच.एल. आहलूवालिया

(पिछले अंका ते अग्गे)

मानसिक हिल्लण

हुण तुसां दिखा दुनिया दियां लोकां च ज्यादा पैसा वधी गिया–माहणुआं दियां विचारां च जमीन कने आसमाने दा अन्तर आई गिया है। मां–पियो कने साड़ी सरकार सारयां जो ही साक्षर वणाणे वास्तें अपणा ऐड़िया चोटिया तिकर जोर लगा करदी। लेकिन असली शिक्षा तां फिरी भी बड़ी दूर, तिसा तिकर तां पुजणे वाले वड़े थोड़े हुन्दे हन। तुसां रोज ही अखवारां च पढ़दे कि अज दुनियां च आत्महत्या करने वाले ज्यादातर पढ़ियो लिखियो ही लोक हुन्दे हन। अजकले दियां पढ़ाईयां दा ऐह हाल। पढ़ाईया दा मतलब जां मकसद कोई जयादा ही डिप्लोमयां यां डिग्रियां ही ासिल करना नीं हुन्दा। अगर पढ़े लिखियो इन्सान अपणे दिमागे दियां शक्तियां ते अणजाण रैहण, हरेक विचारे पर अमल नीं करी सकण, अपणे अन्दर उठियां गल्त विचारां दी परख नीं करी सकण, जिन्हां दे खरे खोटे नतीजे पर गौर नीं करि सकण, तां क्या फाईदा होईया इसा इतणियां बड़िया पढ़ाईया दा। तिसा ते तां अणपढ़ ही खरे, जेहड़े कम से कम अपणियां बुद्धिया ते कम्म लैणे वाले हुंदे हन। अगर विद्या पढ़ियो आदमी भी इसा बुद्धिया दा भी कने इस्तेमाल च लियोणा शुरू करी दिन तां फिरी सुन्ने पर सुहागे वाली गल होई। पढ़ाईया दा अर्थ अपणियां मानसिक शक्तियां, अपणियां बुद्धिया दा विकास, अपणे आत्मा दियां शक्तियां दा विकास, अपणे आपे दी पछैण करने दी कोशिश कि इस इनसानी जन्म लेणे दा क्या मकशद है इसजो जाणना है। अच्छियां- बुरयां विचारां दी परख कसौटीया पर करनी है। संयम वर्तणा है। जियां जे शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक तां ही असां इसा जिन्दिगिया दा जीवनो दा सार समझी सकदे हन। जयादा अमीरिया हासिल करी या ज्याद दौलता, जां नौटां जोड़ी करी, जां ज्यादा महलां पाई इसा जिन्दिगिया दे मकशदे जो नीं समझी सकदे। अगर धरतिया पर आदमियें जो अगर कुसी किसमां दिया मुश्किला कने रूवरू होणा पेई जाऐ तां धीरजे कने सब्रे कने कम लैणा चाहीदा। जियां जे तुसां किंग ब्रूस एण्ड स्पाईडरे दी कहाणी पढ़ियो होणी, नैपोलियन वोनापार्टे दे बारे पढ़िया हूणा, अब्दुल रहीम खानाखान दे बारे पढ़िया हूणा, हरीशचन्द्र विद्यासागरे दे वारे पढ़िया हूणा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दे वारे पढ़िया हूणा। महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविन्द सिंह जी दे वारे पढ़िया हूणा कि तिनहां अपो जिन्दिगिया च औणे वालीयां मुशीवतां दा कियां साहमणा किता पर फिरी भी हिम्मत नीं हारी। हार नीं मन्नि। महाराणी लक्षमीबाई, सति सावित्री, श्री सुभाष चन्द्र बोस, वीर सावरकर, सरदार भगतसिंह वगैरा–वगैरा दा साड़े देशे दे इतिहासे च नां अमर है। ठीक इसी तरीके ने सरदार पटेल, महात्मां गांधी जी भी साड़े देश दे इतिहासे च अमर हन। अज इनहां मिशालां जो साहमणे रखी करी इन्हां दे जीवने ते शिक्षा लैणी है। एकलव्य दिया जीवन शैलिया ते शिक्षा लेणी है। जिसजो गुरूयें शिक्षा देणे ते ही इनकार करी दितया था। यानी सारा जीवन ही कसौटियां कने भरिया है। जियां जे काई सराफ सोने जो अपणियां भट्ठिया पर तपाई तपोई करी खरे खोटे सोने दी परख करदा है। ठीक इसी हालें कुदरत भी सांजो इसा धरतिया पर बार–बार परखदी है। जीणे ते मुंह मोड़ी के जां आत्महत्या करी के कोई मंजिल जां समस्या अजेतिकर कोई हासिल नीं करी सकिया। ऐह कम तां अकला ते हीन जां कायरां जां नार्मदां दा ही गिणियां जान्दा है। सूरमें जो नीं शोभा दिंदा, इन्सान जो कदी भी अपणा दिल नीं छड्डणा चाहीदा। अमीरी गरीबी तां लगियो ही रैहन्दी कने दुख, सुख भी, कने हार–जीत, पास–फेल। ऐह इक हवा है। सदा कोई भी हालत टिकाऊ नीं रैहन्दी। हमेशा सांजो अपणियां विचारां जो डिगाणा नीं चाहीदा, हमेशा तिनहां जो ऊंचा रखी के जीवन व्यतीत करना चाहिदा। इसजो मनोवैज्ञानिक जीणे दी

शैली भी बोलिया जान्दा। फिरी तां नां गरीबिया दा पता लगदा नां ही बेरोजगारिया दा। अगर बच्चा इम्तिआनें विच फेल होई जाऐ तां तिसजो अपणे दुगणे आत्मबले कने तियारी करने दी कोशिश करनी चाहीदी। जिन्दिगी मजबूत इरादियां दा नां है। ऐह कोई निरीह पढ़ाई ही नीं है बल्कि जीणे दी न्यारी कला ही है, इक सुनैहरा सुपना है। अपणा इतिहास अप्पुं ही रचणे दी इक बेहतर कला है। फिरी इसा कला दा रचनात्मक विकास करना ही साड़ी जिन्दिगी है।

सांस्कृतिक हिल्लण

अज तुसां दिखा दे हुंगे कि साड़े देशे च इन्हां अठां–दसां सालां च कितणा दुनिया दा रंग बदल गिया है। सादापन तां तकरीवन पुराणियां उमरा दियां बर्जुगां दे बसे दी ही गल होई गेई। खाणे पीणे दियां चीजां दिखा, कितणा बदलाव आई गिया। कुत्थी दाल रोटी, फुल्का, साग, छल्लियां दी रोटी भात्ते बगैरा हे लोक शौकीन थे। अज दिखा फास्ट फूड, वर्गर, मोमिन, कुथी चौमिन, सलाद आई गै। यानी खाण पाण भी सादा नी रिहा। पहलें वाले बजुर्ग हुक्का चिलम जां कली रखदे थे तम्बाकू पीणे वास्तें। गिया सैह भी रीति रिवाज। अज तुसां दिखा छोटी पीढ़ी कितणी एडवासं होई गेई है सैह कुत्थी गुटखे, गोल्डन खैनीया, यानी नशियां दा हल्ली ही सेवन शुरू करी दितिया है। वणगा क्या? हुण तुसां दिखा पहले बजुर्गां वाले टैमें दारू पीणे वाले वड़े घट मिलदे थे। अज दारूऐ दे ट्रकां दे ट्रक खप्पी जा करदे इतणियां तां कैमिस्टां वाल्ह दवाईयां भी रोज नीं बिकदियां। हुण छोटीया पीढ़िया जो भी दारूऐ दा चस्का पेई गिया है। दारूऐ बगैरा सिधे मुंऐं कोई गल भी नीं करदा। कुसी भी चाई–पाणिये दिया दुकानां च, छोटे मोटे होटले च दिखी लिया। कोई भी दारूऐ वगैर नीं वचिया। कईयां जो भ्यागा ही चाई पीणे दा शौक हुन्दा था– आज सैह भी कई भियागा ही घुट्टे पीणे पर आई गियो हन, कुत्थु चली गेई साड़ी बुद्धि। सब नशोड़ ही होई गै। संन्जा हुन्दिया–हुन्दिया ही तुल होई जादे। चलणे दी होस नीं। पंगिया करी सटा दे। कई कलहां दे मामले तां इंयां ही होआ करदे हन। घरां विच भी शान्ती नीं रेही ना वरकत। कईयां दे गृहस्थी जीवन भी इस ही हालें उजड़ी जा करदे। कंकाल होई जा करदे सैह। हुण तुसां फैशने दे पासं ही दिखा। अज कुत्थु चली गिया खद्दर, लट्ठा, मलेशिया कने पापलीना दा कपड़ा। वस ऐह भी पुराणा फैंशन रिया। पहले लोक कच्चियां घरां च रेही के भी गुजारा करी लैंदे थे। हुण जिन्हां वाल्ह खरा पैसा आई गिया सैह पक्के कोठे बगैरा नीं रैहन्दे। कोठियां दियां रंगा–ढंगां दि खण तां वैकुण्ठ भी हिली पौणा। अज फिल्मां दे पासें दिखा, इकी किसमी दी बाढ़ ही आई चुकियो है। कोई भी घर टैलीविजने कने वीसीआर वगैर नीं मिलदा। रेडियो फैशन पुराणा होई चुकिया। इनीं फैशनें तां दुनियां ही बदली के करी रखि दिती। ऐही गेई कसर तिसजो सीड़ियां पूरा करदियां कने कामेडी फिल्मां तां लोकां दयिा बुद्धिया दा ही कने चाला–चलणे दा ही दिवाला कढणा लाईया। ऐह सांस्कृतिक हिल्लण नीं तां होर कया है?

शरीरी हिल्लण

तुसां दिखा ही करदे हुंगे कि अज जो कुछ भी सांजो खाणे–पीणे, पेट भरने वास्तें मिला करदा जहरीलियां तत्वां दा जरूर कुछ ना कुछ अंश हुन्दा है। जियां जे असां दुध पीन्दे हन। तुसां दिखा कुसी टायमें साड़े सियाणें पशुआं जो घाह–पट्ठा पराली, जंगली घाह, सरूंआ दी खला, अलसिया दी खला, विनौले दी खल, खुआन्दे थे। अज दिखा फीडा दा जमाना आई गिया है। इन्हां फीडां च कई किस्मां दियां गेसां होर तां होर यूरिया तिकर विच दिया हुन्दा है। इस दूधे पीकरी साड़े शरीरे पर क्या असर पौन्दा हुंगा? साड़े देशे दे महान वनस्पति विज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस जी ने भी ऐह सिद्ध करी के दसी दितिया था कि हरेक वनस्पति जियां जे साग, सब्जी, पौधे, फूल, फल इनहां च भी जान हुन्दी हैं अगर इन्हां पर ही जहरीलियां दवाइयां, कीटनाशक दवाइयां दा छिड़काव होआ दा है अगर असां इनहां जो इस्तेमाल करदे हन तां साड़े शरीरे प क्या असर हुन्दा हुंगा? साड़े दिमागे पर क्या असर हुन्दा हुंगा? अज तुसां शरीरे दियां बिमारियां गिणी के दिखा तां एहो दियां पुराणे बजुर्गां दे टायमें नीं सुणियां ना होईयां जिंया जे– ब्लड प्रेशर, पैप्टिक अल्सर, कैंसर, एड्स, ब्लड कैंसर आदि...। कईयां किस्मां दियां अंग्रेजी दवाईयां दा इस्तेमाल करा दे। कई किसमां दे इसा धरतिया पर कैमिकल्स टैस्ट होआ करदे, एटामिक एनर्जी टैस्ट होआ करदे, न्यूक्लिर टैस्ट होआ करदे हन, कई किसमां दियां गेसां पैदा होआ करदियां। जिन्हां दा असर इस वायुमण्डले विच समाई जा करदा, पाणी भी इसा धरतिया पर सैही, हवा भी सैही–पर इस विच जेहड़ा बदलावा आई गिया ऐह कुनी दिखया असां स्वाश लैंन्दै अज ऐ भी सुरक्षित नीं रिया। सारा वर्ल्ड ही कैमीक्लस वणी के रेही गिया।

(मुक्की गया)

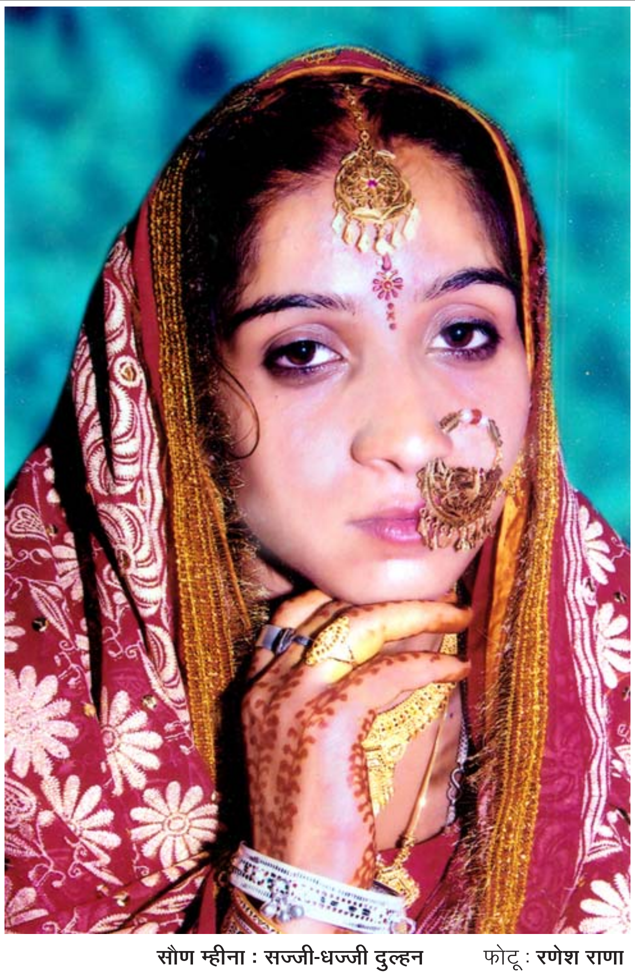

सौण म्हीना : सज्जी-धज्जी दुल्हन फोटू : रणेश राणा

कबता

चांहिदा

गलाणा बुलाणा ढंगे दा होणा चांहिदा
रहणा सहणा साफ सुथरा होणा चांहिदा,
खाणा पीणा दसां नैं दी कमाइया दा
होणा चांहिदा।
ध्यान हर वक्त परमात्मा खा होणा चांहिदा।
बालकां जो संस्कार खरे देणे चांहिदे
बुजुर्गों दा मान सम्मान करना चांहिदा
मेहमान घरे आओ तियूडी मथे
पाणी नी चांहिदी
हासदे हासदे घर आए दा सत्कार
करना चांहिदा।

कुडियां चिड़ियां जो अज दे जमाने
प्यारे कने पढ़ाना लिखाणा चांहिदा,
छैल जेहा समाज बनो इस खातर
सोच विचार कदे रैहणा चांहिदा।

चुगली चापलूसी ते दूर रैहगा चांहिदा
अहंकार नेड़े नी औणे देणा चांहिदा
अंत समय जिंदगिया दा आवे
कुछ बुरा नी कमाया, ऐ सोची के
सच्चे दरबार जाणा चांहिदा।

कुलदीप चंदेल

रैगिंग के खिलाफ निगरानी रखने के लिए स्थापित होंगे अनुश्रवण प्रकोष्ठ

प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव ने प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में रैगिंग जैसी दुष्प्रवृत्ति समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्रीमती राव गत दिनों शिमला में राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं।

श्रीमती राव ने कहा कि गत कुछ माह में शिक्षा संस्थानों में बार-बार रैगिंग की बढ़ती घटनाओं से आभास होता है कि इन संस्थानों में रैगिंग के मामले बढ़ रहे हैं। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टाण्डा में इस वर्ष मार्च माह में हुई दुर्भाग्यपूर्ण रैगिंग की घटना हमें एक बड़ा सबक देती है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से पहले ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। इसके बाद मार्च माह में ही हिमाचल प्रदेश शिक्षण संस्थान (रैगिंग रोकथाम) अध्यादेश-2009 लागू किया गया। उन्होंने विधि तथा पुलिस विभागों को भी निर्देश दिए कि अध्यादेश की कानूनी कार्यविधि तथा क्रियान्वयन करने में किसी प्रकार की कमी का पता लगाएं। राज्यपाल ने सरकार का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 8 मई, 2009 के उस निर्णय की ओर आकर्षित किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राघवन कमेटी की कुछ संस्तुतियों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया था। राज्यपाल ने जानकारी दी कि महामहिम राष्ट्रपति ने हाल ही में सभी राज्यपालों को पत्र लिखकर सभी राज्यों में इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसी दृष्टिगत इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

> ▸ प्रत्येक संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी व स्कवायड
> ▸ उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी

राज्यपाल ने कहा कि वरिष्ठ छात्रों द्वारा नव आगुंतक विद्यार्थियों के साथ शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के मामले समाज के लिए गंभीर मामले हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार तथा कुलपतियों से शिक्षा संस्थानों में इस तरह के अमानवीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए प्रभावी पग उठाने को कहा।

उन्होंने प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालयों का आह्वान किया कि वे राघवन कमेटी की संस्तुति के अनुसार 'एंटी रैगिंग कमेटी' तथा 'एंटी रैगिंग स्कवायड' को प्रत्येक संस्थान में गठित करना सुनिश्चित बनाएं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय 'एंटी रैगिंग कमेटी' अधिसूचित की जानी चाहिए।

उन्होंने कुलपतियों से विश्वविद्यालय स्तर पर अनुश्रवण प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए कहा, ताकि संबद्ध कालेजों एवं संस्थानों में रैगिंग के खिलाफ उपायों की निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की अध्यक्षता में अनुश्रवण प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापित अनुश्रवण प्रकोष्ठ तथा जिला स्तर पर 'एंटी रैगिंग कमेटी' से इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त करेगी।

प्रधान सचिव स्वास्थ्य श्री दीपक सानन, प्रधान सचिव शिक्षा डॉ. पी.सी. कपूर, पुलिस महानिदेशक श्री जी.एस. गिल, हि.प्र. विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील गुप्ता, चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डॉ. तेज प्रताप, हि.प्र. बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन, के कुलपति डॉ. के.आ. धीमान, जे.पी. विश्वविद्यालय वाकनाघाट के कुलपति डॉ. वाई. मदुरै, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. जयश्री शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टाण्डा के प्रधानाचार्य डॉ. अनिल चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

26/11 आपरेशन के नायक की मुख्य मंत्री से भेंट

मुंबई के ताज होटल से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए चलाए गए 26/11 ऑपरेशन ताज का नेतृत्व करने वाले ब्रिगेडियर जी.एस. सिसोदिया जो कि शिमला जिला के चौपाल क्षेत्र से संबंधित हैं, ने गत दिनों शिमला में मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल से भेंट की। मुख्य मंत्री ने ऑपरेशन ताज का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए ब्रिगेडियर सिसोदिया को बधाई देते हुए कहा कि उनके इस योगदान को देशवासी सदैव याद रखेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश को ब्रिगेडियर सिसोदिया के अनुभवों से अवश्य लाभ प्राप्त होगा।

सहकारी सभाओं को सुदृढ़ करने का आग्रह

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ के संचालक मंडल के सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल गत दिनों विकास संघ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य मंत्री को हि. प्र. राज्य सहकारी विकास संघ शिमला द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मुख्य मंत्री को अवगत करवाया गया कि सहकारी मुद्रणालय द्वारा राज्य की सहकारी संस्थाओं, निगमों, हि. प्र. विश्वविद्यालय, साईंस एवं टैक्नोलॉजी जैसी कई अन्य संस्थाओं का मुद्रण कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य मंत्री से प्रदेश में कार्यरत सहकारी सभाओं को सुदृढ़ करने का आग्रह किया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कल्याण आयोग का हिमाचल दौरा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री बूटा सिंह ने गत दिनों शिमला में प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे बैठक की।

श्री बूटा सिंह ने कहा कि राज्य की कुल आबादी में 24.72 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं, जिनकी साक्षरता दर 70.30 है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों का तीव्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित बनाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाना चाहिए तथा कहा कि इस कार्य में स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी संगठनों का सक्रिय योगदान लिया जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी ने आयोग के अध्यक्ष का हिमाचल आगमन पर स्वागत करते हुए प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

वाकनाघाट में खुलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का...

(पृष्ठ एक का शेष) तैयार राहत एवं पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना को कार्यान्वित करना होगा। मंत्रिमण्डल ने अफ्रंट प्रीमियम जमा करने के लिए सैली (320 मेगावाट), कुलिंग 40 मेगावाट, मेने नादंग (70 मेगावाट), लारा (60 मेगावाट), किल्ही बाहल (7.5 मेगावाट) स्यूल (13 मेगावाट) तथा डुग्गर (236 मेगावाट) के निष्पादकों को 30 दिन का समय विस्तार देने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि सभी पात्र निविदा दाताओं को साच खास (149 मेगावाट) तथा रियोली डुगली (420 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उच्चतम बोली के बराबर निविदा की अनुमति प्रदान की जाए। मंत्रिमण्डल ने राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में सेकण्डमेंट आधार पर फैकल्टी सदस्यों के दो पद, ग्रामीण विकास विभाग में सेवानिवृत्ति आधार पर खण्ड विकास अधिकारी का एक पद तथा कृषि विभाग में अनुबंध आधार पर सांख्यिकी सहायकों के 13 पद सृजित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में एक समय की छूट प्रदान कर 48 वर्क इंस्पेक्टरों तथा सर्वेयरों, जिनके पास नागरिक अभियन्ता का डिप्लोमा है, पदोन्नत करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय अक्षम वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद के पक्ष में राज्य सरकार ब्लाक गारंटी को पांच करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये करने तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के पक्ष में 6 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला में कालुझण्डा मधाला सड़क (मधाला चौक) के नानकपुर तथा बरोटीवाला मार्ग (निकट ट्रक यूनियन) रामपुर जग्गी नामक स्थानों पर दो टोल टैक्स बैरियर खोलने पर स्वीकृति प्रदान की ताकि हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट, 1975 के अन्तर्गत कर चोरी को रोका जा सके। मंत्रिमण्डल ने ग्रामीण विद्या उपासकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को 2010-11 तथा 2011-12 से प्रीपोन कर 2009-10 तथा 2010-11 करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के नूरपुर में उप कारागार खोलने को अनुमति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों को रिप्लेसमेंट आधार पर 12 वाहन खरीदने, खण्ड विकास अधिकारियों को विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 9 वाहन खरीदने, पुलिस विभाग को कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है।

सरकार अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों...

(पृष्ठ एक क शेष) सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति उप योजना को तैयार तथा कार्यान्वित करने में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा योजना आयोग से समय-समय पर मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश प्राप्त होते हैं, जिनका प्रदेश सरकार द्वारा अक्षरश: पालन किया जा रहा है। मुख्य मन्त्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं तथा इस दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक भीमराव अम्बेडकर भवन निर्माण के लिए नयी योजना आरंभ की है, जिसके तहत प्रत्येक भवन के निर्माण पर 10 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य में 30 स्थलों का चयन कर लिया गया है तथा शेष के लिए प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में हरिजन आबादी बाहुल क्षेत्रों में 2.50 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी भवन तथा 5 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक केन्द्र निर्मित किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत गत वर्ष आबंटित की गई 2.37 करोड़ रुपये की राशि का पूरा उपयोग किया गया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने पूर्व शासनकाल में अनुसूचित जाति बाहुल बस्तियों में नागरिक सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य से 'गुरु रविदास योजना' आरंभ की थी। योजना के तहत गत वर्ष के दौरान 11.70 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

मुख्य मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित बी.पी.एल. परिवारों को कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड ऍलाइड ऐक्टीविटीज़ के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए इस वर्ष से एक नयी योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत इस वर्ग के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1000 रुपये की छात्रवृत्ति तथा विभिन्न कार्यालयों में 'प्लेसमैंट' के दौरान 1500 रुपये मासिक प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ग्रामीण आवास योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत नये घर के निर्माण के लिए 38,500 रुपये तथा मरम्मत के लिए 15 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत गत वर्ष के दौरान नये घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को 18 हजार से बढ़ाकर 38 हजार तथा मरम्मत के लिए 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति प्रार्थियों को बुनाई-कढ़ाई एवं सिलाई के प्रशिक्षण के लिए 950 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है तथा इस योजना के तहत गत दो वर्षों में 1.54 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम द्वारा इन वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, ताकि इन वर्गों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा लाभान्वितों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर 50 हजार रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं तथा प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जाति के 4385 तथा अनुसूचित जनजाति के 775 लाभान्वितों को ऋण सुविधा प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि हिम स्वावलम्बन योजना के तहत टैक्सी तथा बसें इत्यादि खरीदने के लिए 5 लाख रुपये तक उच्च ऋण 6 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा 30 लाख रुपये तक के ऋण 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को 75 हजार रुपये से 2.50 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत वाल्मीकि समुदाय के छात्रों को दसवीं कक्षा से विश्वविद्यालय स्तर तक 9000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। डॉ. अम्बेदकर छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के 1 हजार मेधावी छात्रों को 10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के उपेक्षित एवं कमजोर वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल हैं, के तीव्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा यह भविष्य में भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल रहेगा।

राज्य वन प्राणी संरक्षण बोर्ड गठित

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड का गठन किया है। मुख्य मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जबकि वन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। विधायकगण सर्वश्री गोविन्द ठाकुर, डॉ. रामलाल मारकण्डेय तथा तेजवंत नेगी इसके सदस्य होंगे, जबकि मुख्य संसदीय सचिव श्री सुखराम, विधायकगण सर्वश्री रणधीर शर्मा, बी. के. चौहान, गोविन्द शर्मा तथा प्रवीण शर्मा बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, सचिव जनजाति कल्याण, प्रबन्ध निदेशक हि.प्र. पर्यटन विकास निगम, पुलिस महानिरीक्षक, ब्रिगेडियर प्रशासन, आरट्रैक शिमला, निदेशक पशुपालन, निदेशक मत्स्य पालन, भारत सरकार के निदेशक वन्य प्राणी संरक्षण के प्रतिनिधि, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून के प्रतिनिधि, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के प्रतिनिधि इसके सरकारी सदस्य होंगे, जबकि मुख्य वार्डन वन्य प्राणी इसके संयोजक सदस्य होंगे। 'वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा 8 तथा इसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसान राज्य वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड अपने कार्यों एवं दायित्त्वों का निर्वहन करेगा।

बीस सूत्री कार्यक्रम...

(पृष्ठ एक का शेष) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया। अनुसूचित जाति के परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए प्रदान की गई सहायता के मामले में भी राज्य की उपलब्धि बहुत अच्छी रही है। इस समयावधि में लगभग 49000 परिवारों को सहायता प्रदान की गई। एकीकृत शिशु विकास कार्यक्रम के सार्वभौमीकरण के अन्तर्गत राज्य की उपलब्धि इस समयावधि में 101 प्रतिशत तथा आंगनबाड़ियों को क्रियाशील बनाने में राज्य की उपलब्धि 100 प्रतिशत रही है।

वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की उपलब्धि 102 प्रतिशत रही है। राज्य में इस समयावधि में 18,326 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 18,705 हेक्टेयर क्षेत्र पौधरोपण के अन्तर्गत लाया गया और 1.19 करोड़ पौधे रोपित करने के लक्ष्य के मुकाबले 1.21 करोड़ पौधे रोपित किए गए। गरीबी उन्मूलन को लक्षित कर बनाई गई इस योजना के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश की अभूतपूर्व उपलब्धियां यह सिद्ध करती हैं कि प्रदेश सरकार आम व्यक्ति विशेषकर गरीब तथा उपेक्षित व्यक्तियों के कल्याण की दिशा में पूर्ण तत्परता तथा समर्पण की भावना से कार्य कर रही है।

सेना भर्ती कोटे में वृद्धि का मामला केन्द्र से उठाया जाये-राज्यपाल

सैनिकों के कल्याण के प्रति सरकार वचनबद्ध

राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव ने सशस्त्र सेनाओं में हिमाचल प्रदेश के भर्ती कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह मामला भारत सरकार के साथ प्रभावशाली तरीके से उठाया जाना चाहिए। श्रीमती राव गत दिनों शिमला में राज्य सैनिक बोर्ड की 22वीं तथा प्रशासनिक राज्य प्रबंधन समिति की 40वीं बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न सैन्य ऑपरेशनों में हिमाचल के सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों के उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को रक्षा सेवाओं में और अधिक अवसर प्रदान किये जाने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर 'वन रैंक-वन पेंशन' के मामले को प्रभावशाली तरीके से उठाए जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे। राज्यपाल ने राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक, मंत्री की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि राज्य में चलाए जा रहे विभिन्न सैनिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें सशस्त्र सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जा सके।

मुख्य मंत्री प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के वार्षिक मानदेय में समय-समय पर वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि नए शौर्य पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार, वार्षिकी तथा भूमि के एवज में अनुदान के स्थान पर एक मुश्त एक बारगी अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र तथा अशोक चक्र विजेताओं को 25 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान, महावीर चक्र तथा कीर्ति चक्र विजेताओं को 15 लाख रुपये, वीरचक्र तथा शौर्य चक्र विजेताओं को 10 लाख रुपये की एक मुश्त अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों की वृद्धावस्था पैंशन को इस वित्त वर्ष से बढ़ाकर क्रमशः 200 रुपये से 330 रुपये तथा 200 से 550 रुपये किया गया है तथा जो भूतपूर्व सैनिक निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके अनुदान को 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त युद्ध जागीर को 900 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में हिमाचल प्रदेश के सैनिकों का सर्वाधिक योगदान है तथा भारतीय सेना में प्रदेश के 1,20,590 सेवारत सैनिक, 1,01,057 भूतपूर्व सैनिक, 1048 युद्ध विधवाएं, 25573 अन्य विधवाएं, 3,75,460 भूतपूर्व सैनिकों के अन्य आश्रित तथा 1,25,250 परिवार सेवारत सैनिकों पर आश्रित हैं।

मुख्य सचिव श्रीमती आशा स्वरूप ने ऊना में स्वतंत्र सीएसडी डिपू तथा ऊना जिले के मुबारिकपुर तथा मंडी जिले के सरकाघाट में दो और पॉली क्लीनिक स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि भूतपूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य एवं अन्य सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। उद्योग मंत्री श्री किशन कपूर, जिनके पास सैनिक कल्याण विभाग भी है, उपस्थित थे।

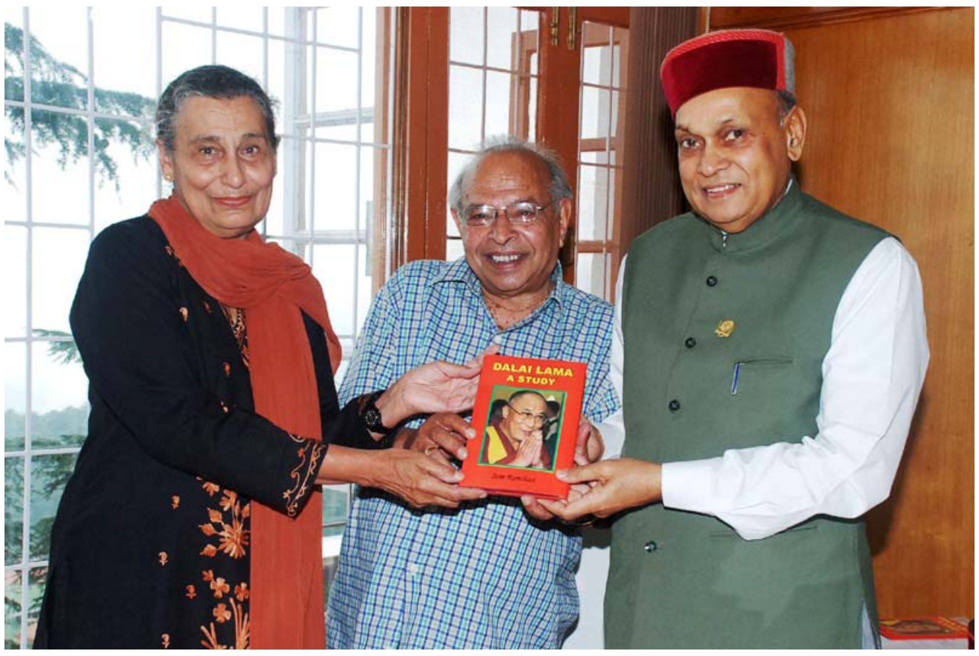

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल शिमला में विख्यात शिक्षाविद् प्रो. सोम पी. रंचन द्वारा लिखित पुस्तक 'दलाई लामा ए स्टडी' का विमोचन करते हुए।

पॉलीहॉउस निर्माण सम्बन्धी समस्याओं का समाधान दूरभाष पर

'पंडित दीन दयाल किसान-बागबान समृद्धि योजना' के अंतर्गत पॉलीहॉउस के निर्माण के सम्बन्ध में किसान किसी भी समस्या का समाधान सचिव तथा निदेशक कृषि के कार्यालय से दूरभाष पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सचिव कार्यालय से मोबाइल नम्बर **94180-73700** पर रविवार व सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। इस मोबाइल नम्बर पर एसएमएस भी किया जा सकता है। कृषि निदेशक से भी कार्यालय दिवस में फोन नम्बर **0177-2830517** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सरकारी प्रिंटिंग प्रेस का होगा आधुनिकीकरण

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री रविन्द्र सिंह रवि, जिनके पास मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का कार्यभार भी है ने कहा कि विभाग राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों एवं निगमों को सभी प्रकार की लेखन सामग्री की आपूर्ति करने के प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि लेखन सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। श्री रवि गत दिनों मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस की कार्य प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए यहां आधुनिक उपकरण एवं आवश्यक विशेषज्ञ तैनात किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यवसायियों एवं तकनीकी कर्मियों को आधुनिक तकनीक के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सचिव, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग श्री बी.एस. नेंटा, नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री श्री राजीव शंकर तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक एवं दौरे के दौरान उपस्थित थे।

जिला स्तर पर विकास योजनाओं को एकीकृत करने पर बल

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम ठाकुर ने योजना के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ विकासात्मक योजनाओं का लाभ गरीब एवं समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री जयराम ठाकुर गत दिनों शिमला में एकीकृत जिला योजना के विषय में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तभी लाई जा सकती है, जब सभी विभागों की योजनाओं को जिला स्तर पर एकीकृत किया जाए। निचले स्तर पर योजना के विकेन्द्रीकरण पर बल देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि जिला स्तर की योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करते समय लोगों की इनमें भागीदारी सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए।

प्रशिक्षण आधारभूत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के संबंध में श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 4.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जिला कांगड़ा के बैजनाथ में एक पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार शिमला जिला के मशोबरा में 5.50 करोड़ रुपये की लागत से संस्थान का सुदृढ़ीकरण एवं स्तरोन्न किया जा रहा है।

श्रीमती राजवंत संधु, विशेष सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अधोसंरचना के विकास एवं सुदृढ़ीकरण में मुख्य कारक रहा है। डॉ. श्रीकांत बाल्दी, सचिव ग्रामीण विकास हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

मुख्य सचिव श्रीमती आशा स्वरूप ने इस दो दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र की अध्यक्षता की।

लोक सेवा आयोग की नई वैबसाइट

सचिव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गत दिनों जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी नई वैबसाइट www.hp.gov.in/hppsc विकसित की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी अधिसूचनाएं एवं विज्ञापन इस वैबसाइट पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक प्रार्थी आयोग की नई वैबसाइट से सूचना प्राप्त कर सकता है।

खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है युवा क्रीड़ा अभियान से

छः जिलों में क्रिकेट स्टेडियमों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में गुणात्मक खेल अधोसंरचना का सृजन करेगी ताकि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरकर प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकें। राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान मनाली में कृत्रिम 'रॉक क्लाइंबिंग' दीवार बनाई जाएगी और मनाली के समीप एल्पाइन ग्रास स्कीईंग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। यह जानकारी मुख्य मंत्री प्रो. कुमार धूमल ने गत दिनों शिमला में युवा सेवाएं एवं खेल तथा अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि खेल संघ अनुदान को 'ए' श्रेणी के लिए बढ़ाकर 75 हज़ार रुपये, 'बी' श्रेणी के लिए 50 हज़ार रुपये और 'सी' श्रेणी के लिए बढ़ाकर 35 हज़ार रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि युवा एवं खेल सेवाएं तथा सामाजिक जागरुकता की गतिविधियों में युवक मंडलों को जोड़ा जाना चाहिए। राज्य में 3500 युवक मंडल पंजीकृत हैं जो युवा ऊर्जा को रचनात्मक एवं सृजनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में सभी स्तरों पर गुणात्मक खेल आधारभूत अधोसंरचना विकसित करने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी ज़िलों में मूलभूत खेल गतिविधियों के लिए आवश्यक अधोसंरचना सृजित की जाएगी जिनमें जिम्नेजियम और राज्य क्रिकेट संघ के सहयोग से बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला सिरमौर, चम्बा, शिमला, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और ऊना में प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। हमीरपुर और धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक ट्रैक बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 77 खंडों में वर्ष 2008-09 से 2016-17 की अवधि के लिए पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान आरंभ किया गया है। इसके लिए 7215.54 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

प्रो. धूमल ने कहा कि विशेष घटक योजना के तहत राज्य में 346 खेल मैदान निर्मित किए गए हैं और वित्तीय प्रोत्साहन की राशि 50 हज़ार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। राज्य में स्टेडियमों के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों को एक लाख रुपये की 'सीड केपिटल ग्रांट', सभी खंड पंचायतों को मिलने वाली 5 लाख रुपये की एक समान वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों और कार्य शिविरों के लिए 50 लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने युवाओं एवं खिलाड़ियों के लिए राज्य के भीतर मिलने वाले खुराक भत्ते को 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये और राज्य से बाहर इसे 60 से बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव की स्वर्ण पदक विजेता सुश्री पुष्पा ठाकुर, संजो देवी और आरज़ू को 50-50 हज़ार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है और अभी तक 171 खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल चुका है। प्रो. धूमल ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान विश्वस्तरीय है और विश्व भर से साहसिक खेलों के प्रेमी यहां विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक स्वायत्त संस्थान है और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्व जुटा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पर्यटन विभाग के सहयोग से ज़िला मंडी की जंजैहली घाटी में साहसिक खेल गतिविधियां आरंभ करने के निर्देश दिए। जंजैहली घाटी में आधारभूत सुविधाएं पहले ही पर्यटन विभाग द्वारा सृजित की जा चुकी हैं।

प्रधान सचिव, युवा एवं खेल सेवाएं श्री वी.सी फारका ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बजटीय प्रावधान को 42 प्रतिशत बढ़ाने पर मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त किया।

प्रकाशकः बी.डी. शर्मा, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र. शिमला–171002, मुद्रकः राजीव कुमार शंकर, नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला–171005, फोनः 2830378, प्रधान सम्पादकः बी.डी. शर्मा, वरिष्ठ सम्पादकः आर.एस. नेगी, सम्पादकः यादविन्दर सिंह चौहान, कार्यालयः हि.प्र. मुद्रणालय परिसर, शिमला–171005, फोन व फैक्सः 2633145, ई–मेलः girirajhp@gmail.com., girirajhp@yahoo.co.in OR girirajweekly 1978 @yahoo.co.in प्राप्ति स्थानः गिरिराज कार्यालय। (गिरिराज साप्ताहिक में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचारों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं)